नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

वर्ष 03, अंक 372, नई दिल्ली, गुरुवार 12 मार्च 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"सच्चाई और न्याय का मार्ग कठिन जरूर होता है,लेकिन अंत में वही मार्ग सम्मान, विश्वास और सच्ची जीत तक पहुँचाता है।"

02 चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल करें घरेलू उत्पाद

06 अब आया स्मार्ट चश्मा: लिखा हुआ पढ़कर सुनाएगा

08 राउरकेला विधानसभा चुनाव मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

India's First Leading English Transport Newspaper
parivahanvishesh

आरएनआई द्वारा दो भाषाओं में अनुमोदित, प्रकाशित समाचार पत्र "परिवहन विशेष" वार्षिक समारोह

दिनांक:- 29 मार्च , स्थान:- मावलंकर हाल, कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, समय:- 1 बजे से 5 बजे

परिवहन विशेष : हिन्दी एवं इंग्लिश भाषा दैनिक समाचार पत्र आपको अपने तृतीय वार्षिक समारोह में सम्मान पूर्वक शामिल होने के लिए निमंत्रित करता है

इस वर्ष का वार्षिक समारोह मुख्य रूप से "सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा" को समर्पित है।

मुख्य विशेषता :

1. विशेषज्ञों द्वारा जानने का प्रयास की भारत सरकार द्वारा देश में सख्त कानून लागू करने के बाद भी बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और सड़को पर उपलब्ध जाम का मुख्य कारण और उससे छुटकारा पाने के लिए क्या नीतियां अनिवार्य,
2. सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया, एनजीटी, वायु गुणवत्ता आयोग एवं सरकारों द्वारा नए नए दिशा निर्देशों, आदेशों के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण होने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है उससे निजात पाने के लिए जाएंगे इस समारोह में विशेषज्ञों से उनके विचार
3. डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते भारत में बढ़ते साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है इसपर पूर्ण चर्चा एवम् विशेषज्ञों की राय
4. भारत दश में नए कानूनों के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार और गुमशुदगी पर गहन चिंतन और विशेषज्ञों के विचार

इस समारोह में भारत देश के ज्वलंतशील मुद्दों पर जानकारी प्राप्त कर समाचार पत्रों द्वारा जनहित में जनता को सचेत करने और उससे जनता की सुरक्षा संभव के लिए *"परिवहन विशेष" " समर्पित एवं पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेगा। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष का वार्षिक समारोह ज्वलंतशील मुद्दों को समर्पित किया गया है। इस समारोह में भारत देश से विशेषज्ञों के साथ - साथ हमारा प्रयास भारत सरकार के माननीय गणमान्य कैबिनेट एवं राज्य स्तरीय मंत्रियों की गरिमा पूर्ण उपस्थिति और उनके विचार जनहित में मुख्य बिंदुओं में रहेगा।

इस समारोह में भारत देश में जनहित में इन कार्यों को करने में पूर्ण निष्ठा से सलग्न "सामाजिक कार्यकर्ताओं और कार्यरत समूहों (एनजीओ, ट्रस्ट एवं एसोसिएशन) को पुरस्कार" देकर सम्मानित किया जाएगा।

आपकी उपस्थिति हमारा गर्व

TRANSPORT VISHESH NEWS LIMITED
www.newsparivahan.com, www.newstransport.in

टेंपल्स आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) वैष्णवी फाउंडेशन एवं द्वारका स्थित मैक्स सुपर हॉस्पिटल के सौजन्य से

"पूर्णता निःशुल्क, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, स्वास्थ्य जाँच शिविर
आपकी तंदुरुस्ती हमारा ध्येय, टोलवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित

पूर्णतः निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर

संजय कुमार बाठला
राष्ट्रीय अध्यक्ष,

* वैष्णवी फाउंडेशन के सहयोग द्वारा

1. आंखों की जांच, 2. रक्तचाप, 3. मधुमेह जांच, 4. मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ 5. भारतीय लेंस की सुविधा * द्वारका स्थित मैक्स सुपर हॉस्पिटल के सहयोग द्वारा 6. बीपी, 7. शुगर, 8. कोलेस्ट्रॉल, 9. हड्डियों का घनत्व,

इस जांच शिविर मे ऊपरलिखित सभी जांच पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
इस जांच शिविर में निम्नलिखित अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टर्स एवम् अन्य की निगरानी में जांच,

वैष्णवी फाउंडेशन: 1. डॉ मनोज कुमार दुबे, 2. रिशु भारद्वाज, एवं 3. विकास राय द्वारका स्थित मैक्स सुपर हॉस्पिटल चिकित्सक 4. जगदीश

जांच शिविर : दिनांक: 15 मार्च (रविवार) 2026
स्थानः गुरुद्वारा सिंह सभा, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, शिवाजी एन्क्लेव, दिल्ली 110027
समय: 10:00 AM to 02:00 PM

आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में समय पर पधारें तथा अपने सगे-संबंधियों और मित्रों को भी साथ लेकर आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएँ।
विशेष जानकारी मोतियाबिंद सर्जरी के साथ-साथ भारतीय लेंस की सुविधा के लिए मरीज को अपने खर्चे पर बालाजी हॉस्पिटल लायन्स हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, पर सर्जरी और भारतीय लेंस निशुल्क रहेगा।
स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। आपकी सेहत- हमारी प्राथमिकता।

निवेदक :-
संजय कुमार बाठला-राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिंकी कुंडू-महासचिव, केके छाबड़ा-उपाध्यक्ष, सुनीता शर्मा-सचिव, अभिषेक राजपूत-सचिव

पिंकी कुंडू
महासचिव

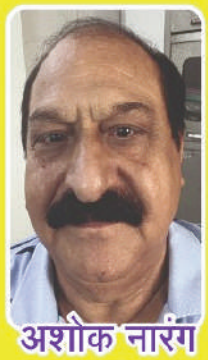
अशोक नारंग
उपाध्यक्ष

के.के. छाबड़ा
उपाध्यक्ष

सुनिता शर्मा
निजि सचिव (महासचिव)

अभिषेक राजपूत
सचिव

जयभगवान
सदस्य

अगर आप भारत देश में निम्नलिखित कार्यों में जनहित को समर्पित है तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं 'परिवहन विशेष' समाचार पत्र के तृतीय वार्षिक सम्मान समारोह में सम्मान

"सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा"
आज ही अपना आवेदन प्रक्रिया पूरी करे, यह बिल्कुल निशुल्क है,
अगर आपकी प्रतिभा इसे प्राप्त करने में सक्षम है तो आवेदन करे
https://www.newsparivahan.com/chief-editor/https://forms.gle/6tTqg7JX4EHGy2Cw9
मुख्य संपादक (परिवहन विशेष)

तृतीय वार्षिक सम्मान समारोह - 2026

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा
के जनहित कार्यों को समर्पित

20 सड़क सुरक्षा
महिला सुरक्षा
प्रदूषण
साइबर अपराध

अगर आप इन क्षेत्रों में जनहित को समर्पित हैं और आपकी प्रतिभा सक्षम है, तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं सम्मान। आज ही बिल्कुल निशुलक आवेदन करें।

दिनांक: 29 मार्च (रविवार) समय - दोपहर 1 बजे 5 बजे तक।
स्थान - कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली, 110001

आवेदन प्रक्रिया
https://forms.gle/6tTqg7JX4EHGY2Cw9

मुख्य संपादक - परिवहन विशेष

धूम्रपान निषेध दिवस (मार्च माह का दूसरा बुधवार)

धूम्रपान दुनिया भर में गंभीर स्वास्थ्य खतरों में से एक है। धूम्रपान के कारण हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। यह न केवल कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बनता है, बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म देता है। इसी वजह से हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके। यह दिवस धूम्रपान और इसके अन्य हानिकारक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

धूम्रपान निषेध दिवस जिसे नो स्मोकिंग डे के नाम से भी जाना जाता है, हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 11 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। बता दें कि जिन लोगों की धूम्रपान करने की आदत होती है, उनके लिए यह आदत छोड़ना या कम करना कठिन हो जाता है। वहीं जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं लेकिन धूम्रपान करने वालों के सम्पर्क में आ जाते हैं, वह भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए इस दिवस के दौरान, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसका उद्देश्य है लोगों को तंबाकू मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना।

>> धूम्रपान निषेध दिवस का इतिहास <<

धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार वर्ष 1984 में यूनाइटेड किंगडम में मार्च माह के पहले बुधवार को मनाया गया था। हालांकि, समय के साथ, यह दिवस दूसरे बुधवार को मनाया जाने लगा। अब यह दिवस पूरे यूनाइटेड किंगडम समेत अन्य देशों में भी एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाये जाने का उद्देश्य था धूम्रपान करने वाले लोगों को हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ने में मदद करना।

>> धूम्रपान निषेध दिवस 2026 का थीम <<

धूम्रपान निषेध दिवस, धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस 2026 की थीम है, ₹अपील का खुलासाः नशे और निकोटीन की लत पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना।₹ इसके विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और प्रचार-प्रसार पर रोक जरूरी है। इससे संबंधित लोगों, विशेष रूप से युवाओं, में सिल्की गुड़िया के प्रति आकर्षण कम होगा। ऑक्सीजन के सेवन से

कैंसर, हृदय रोग और फेफड़े की गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं।

>> धूम्रपान निषेध दिवस का उद्देश्य <<

हर साल धूम्रपान निषेध दिवस कई उद्देश्यों के साथ मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू और धूम्रपान से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करना है।

>> धूम्रपान निषेध दिवस के प्रमुख उद्देश्य <<

* धूम्रपान निषेध दिवस का उद्देश्य धूम्रपान से होने वाली बीमारियों, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और सांस संबंधी समस्याओं के बारे में लोगों को सूचित करना है।
* धूम्रपान करने वालों को इसे छोड़ने के लिए समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना है।
* सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को धूम्रपान रोकने के लिए सख्त नियम और कानून लागू करने के लिए प्रेरित करना है।
* तंबाकू उद्योग द्वारा अपनाई जाने वाली मार्केटिंग रणनीतियों का पर्दाफाश कर युवाओं को इसके नुकसान से बचाना है।
* लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लाभों से अवगत कराना और एक स्वस्थ, धूम्रपान-मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

>> धूम्रपान निषेध दिवस का महत्व <<

एक महत्वपूर्ण अवसर है जो तंबाकू के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

* यह दिवस लोगों को धूम्रपान एवं तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में शिक्षित करता है।
* यह दिवस लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रेरित करता है।
* यह दिवस तंबाकू मुक्त दुनिया के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
* यह दिवस लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
* यह दिवस लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों की जांच के लिए प्रोत्साहित करता है।

जंकफूड, स्ट्रीटफूड और पैकेज्ड फूड के सेवन से से बढ़ रहा किडनी

डॉ रुप कुमार बनर्जी
होमियोपैथिक चिकित्सक

आधुनिकता और शहरी जीवनशैली की तेज़ रफ्तार के साथ हमारे खान-पान की आदतों में भी बड़ा बदलाव आया है। आजकल जंक फूड, स्ट्रीट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जो डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। चाट, गोलगप्पा, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे खाद्य पदार्थ स्वाद, सुविधा और आसानी से उपलब्ध होने के कारण लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इन खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन शरीर के लिए कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, विशेष रूप से किडनी के लिए।

विश्व किडनी दिवस, जो प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, का उद्देश्य लोगों में किडनी के स्वास्थ्य, किडनी रोगों की समय पर पहचान और उनकी रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

किडनी : स्वास्थ्य की मौन संरक्षक :- किडनी हमारे शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं, जो शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। सेम के आकार के ये अंग लगातार रक्त को फ़िल्टर करके शरीर से विषैले पदार्थों और अपशिष्ट तत्वों को बाहर निकालते हैं।रक्त को शुद्ध करने के साथ-साथ किडनी शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने, इलेक्ट्रोलाइट स्तर को नियंत्रित करने तथा रक्तचाप को संतुलित रखने में भी मदद करती है। किडनी की कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पूरे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

जंक, स्ट्रीट और पैकेज्ड फूड कैसे पहुंचाते हैं किडनी को नुकसान ? :- अधिकांश प्रोसेस्ड और स्ट्रीट फूड में अत्यधिक मात्रा में नमक, रिफाइंड तेल, कृत्रिम रंग, प्रिज़र्वेटिव और अस्वस्थ वसा (अनहेल्दी फैट) पाए जाते हैं। लंबे समय तक इनका सेवन किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है।नमकीन स्नैक्स में मौजूद अत्यधिक सोडियम रक्तचाप को बढ़ा देता है, जिससे किडनी की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसी प्रकार अत्यधिक कैलोरी वाले जंक फूड मोटापा और मधुमेह को बढ़ावा देते हैं, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के प्रमुख जोखिम कारक हैं।

पर्याप्त पानी न पीना और अत्यधिक नमक का सेवन किडनी स्टोन (पथरी) की संभावना भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रिज़र्वेटिव और रासायनिक तत्व शरीर में विषैले पदार्थों का बोझ बढ़ा देते हैं, जिससे किडनी को उन्हें बाहर निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही, अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किए गए स्ट्रीट फूड से संक्रमण होने की संभावना रहती है, जो मूत्र मार्ग और किडनी को प्रभावित कर सकते हैं।

किडनी रोग के प्रारंभिक चेतावनी संकेतः- किडनी के रोग अक्सर धीरे-धीरे और बिना स्पष्ट लक्षणों के विकसित होते हैं, लेकिन शरीर कुछ प्रारंभिक संकेत देता है। जैसे-चेहरे या पैरों में

सूजन, पेशाब करते समय जलन, झागदार पेशाब, अत्यधिक थकान, भूख कम लगना, बार-बार या बहुत कम पेशाब आना, कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द। इन लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। समय पर चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक जांच से किडनी रोग का प्रारंभिक चरण में ही पता लगाया जा सकता है।

होम्योपैथिक दृष्टिकोण :- होम्योपैथी में उपचार केवल रोग के आधार पर नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति की प्रकृति, लक्षणों और मूल कारणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उपयुक्त औषधि का चयन रोगी की शारीरिक और मानसिक संरचना के अनुसार किया जाता है।होम्योपैथिक चिकित्सा शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और शरीर की स्वाभाविक उपचार प्रक्रिया को सक्रिय करने में सहायक होती है। हालांकि किसी भी प्रकार की दवा का सेवन केवल योग्य चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए।

किडनी को स्वस्थ रखने के सरल उपाय :- किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ सरल जीवनशैली उपाय अपनाए जा सकते हैं जैसे - दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, जंक फूड, स्ट्रीट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स का सेवन सीमित करें, आहार में ताजे फल, सलाद और हरी सब्जियां शामिल करें, अधिक नमक, चीनी और तले-भुने भोजन से बचें, नियमित व्यायाम या योग करें, शर्करा युक्त और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का सेवन कम करें, समय-समय पर स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं।

बेहतर स्वास्थ्य के लिए संदेश :- किडनी हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जो दिन-रात बिना रुके रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए स्वस्थ खान-पान और संतुलित जीवनशैली अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

विश्व किडनी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि जागरूकता, समय पर जांच और स्वस्थ आदतें अपनाकर किडनी रोगों के बढ़ते खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पौष्टिक भोजन को अपनाना और जंक व प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना दीर्घकालिक किडनी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

जब भी मैं कैंसर से पीड़ित बच्चों के माता-पिता से मिलता हूँ, तो वे गहरे दुःख और पीड़ा के साथ अक्सर कहते हैं:

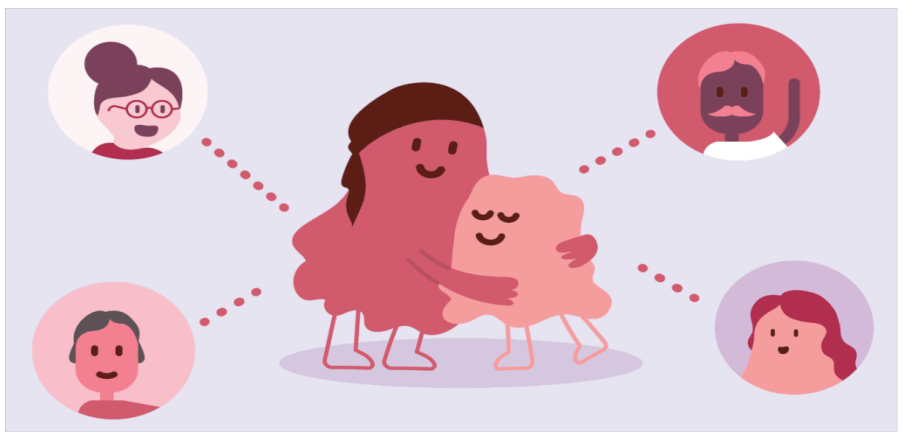

"हमारे बच्चे की कोई भी बुरी आदत नहीं थी। उसने कभी धूम्रपान नहीं किया, न ही गुटखा या तंबाकू का सेवन किया। फिर उसे कैंसर कैसे हो गया ?"

ये भोले-भाले और शोकाकुल माता-पिता अक्सर यह नहीं समझ पाते कि हानिकारक जोखिम केवल धूम्रपान या तंबाकू तक ही सीमित नहीं हैं।

आज की दुनिया में बच्चे अनजाने में कई ऐसे खाद्य पदार्थों और पेयों के संपर्क में आ रहे हैं जिनमें संभावित रूप से कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व छिपे हो सकते हैं—जैसे कृत्रिम रंगों से बने आइसक्रीम, रासायनिक पदार्थों से भरपूर कोल्ड ड्रिंक्स, तथा विभिन्न प्रकार के अत्यधिक प्रसंस्कृत (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड) स्नैक्स।

जो चीज़ें देखने में साधारण और निर्दोष प्रतीत होती हैं, वे कभी-कभी कृत्रिम योजकों, हानिकारक रसायनों और संभावित कैंसरकारी तत्वों से युक्त हो सकती हैं। यदि इनका लंबे समय तक बार-बार सेवन किया जाए, तो वे गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को जन्म दे सकती हैं। माता-पिता का यह दर्दभरा प्रश्न हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई की याद दिलाता है कि आधुनिक समय के अनेक स्वास्थ्य-संबंधी खतरे अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य होते हैं, जो अक्सर हमारे दैनिक आहार की साधारण प्रतीत होने वाली चीज़ों में ही छिपे रहते हैं।

इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि परिवार अपने बच्चों के भोजन और पेय पदार्थों की गुणवत्ता के प्रति जागरूक, सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि आज उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही उनके सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है।

अंकुरित अनाज (Sprouted Foods) एक ऐसा विकल्प हैं, जिन्हें आयुर्वेद में कहा जाता है "जीवनदायी आहार"

अंकुरित अनाज आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई ऐसा भोजन चाहता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ऊर्जा, ताक़त और रोगों से सुरक्षा भी दे। ऐसे में अंकुरित अनाज (Sprouted Foods) एक ऐसा विकल्प हैं, जिन्हें आयुर्वेद में "जीवनदायी आहार" माना गया है। अंकुरित अनाज में छुपा है शरीर को मजबूत बनाने का प्राकृतिक फॉर्मूला, जिसे सही तरीके से अपनाकर हम कई रोगों से बच सकते हैं।

आयुर्वेदिक दृष्टि से अंकुरित अनाज आयुर्वेद के अनुसार, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है। जब कोई अनाज अंकुरित होता है, तो उसमें जीवन ऊर्जा (प्राणशक्ति) जाग्रत हो जाती है।

1. अंकुरण प्रक्रिया से अनाज में एंज़ाइम्स सक्रिय हो जाते हैं।
2. यह भोजन हल्का (लघु), सुपाच्य (आसान पचने वाला) और बलवर्धक (ऊर्जा देने वाला) बन जाता है।
3. चरक संहिता में यह उल्लेख है कि सात्त्विक और ताज़ा आहार शरीर को रोगों से दूर रखता है, और अंकुरित अनाज इसी श्रेणी में आते हैं।

अंकुरित अनाज में पाए जाने वाले पोषक तत्व

1. जब दालें, गेहूं, मूंग, चना आदि अंकुरित किए जाते हैं, तो इनमें मौजूद पोषक तत्व कई गुना बढ़ जाते हैं।
2. विटामिन B, C, और E की मात्रा बढ़ जाती है।
3. इसमें प्रोटीन अधिक सुपाच्य रूप में उपलब्ध होता है।
4. फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज़ से बचाता है।
5. एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री-रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं।
6. इसमें मौजूद खनिज (कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम) हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं।

अंकुरित अनाज के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ

1. पाचन शक्ति में सुधार – ये हल्के होते हैं और पेट को आराम देते हैं।
2. रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि – एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को बीमारियों से बचाते हैं।
3. हृदय की सुरक्षा – खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने और ब्लड प्रेशर संतुलित रखने में मदद।
4. वजन नियंत्रित करें – फाइबर और प्रोटीन से लंबे समय तक पेट भरा रहता है।
5. सुंदर त्वचा और बाल – विटामिन E और जिंक त्वचा को निखारते हैं और बालों को मज़बूती देते हैं।
6. डायबिटीज़ कंट्रोल – अंकुरित दालें शुगर लेवल को संतुलित रखती हैं।
7. मानसिक स्वास्थ्य – विटामिन B-कॉम्प्लेक्स तनाव कम करने और मस्तिष्क को सक्रिय रखने में सहायक।

घरेलू उपयोग और सेवन के तरीके

1. सुबह के नाश्ते में – एक कटोरी अंकुरित मूंग या चना नींबू और काली मिर्च डालकर खाएं।
2. सलाद के रूप में – प्याज़, टमाटर और धनिया डालकर स्वाद बढ़ाएं।
3. हल्के उबालकर – जिन्हें कच्चा खाना भारी लगता है, वे इन्हें उबालकर खा सकते हैं।
4. बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए – दही या छाछ में मिलाकर सेवन करें।
5. अत्यधिक गैस या अपच वाले लोग – थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं।

सावधानियां

1. अंकुरित अनाज हमेशा ताज़ा ही खाएं, बासी अंकुरित दाने आम (टॉक्सिन्स) उत्पन्न कर सकते हैं।
2. रात में इनका सेवन ना करें, क्योंकि यह ठंडे (Sheetal) गुण वाले होते हैं और पचने में समय लग सकता है।
3. जिनको गंभीर वात रोग (जोड़ों का दर्द, गैस, पेट फूलना) है, उन्हें इन्हें हल्का उबालकर खाना चाहिए।

निष्कर्ष अंकुरित अनाज केवल एक साधारण आहार नहीं बल्कि शरीर को निरोगी और ऊर्जावान बनाने का अमृत हैं। आयुर्वेद कहता है कि "यथा अन्नं तथा मनः" – जैसा आहार होगा, वैसा ही मन और स्वास्थ्य होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं फिटनेस, सुंदरता और दीर्घायु – तो अंकुरित अनाज को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें।

नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

परिवहन विशेष

www.newsparivahan.com

वर्ष 03, अंक 372, नई दिल्ली, गुरुवार 12 मार्च 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

"सच्चाई और न्याय का मार्ग कठिन जरूर होता है,लेकिन अंत में वही मार्ग सम्मान, विश्वास और सच्ची जीत तक पहुँचाता है।"

02 चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल करें घरेलू उत्पाद

06 अब आया स्मार्ट चश्मा: लिखा हुआ पढ़कर सुनाएगा

08 राउरकेला विधानसभा चुनाव मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

जल शक्ति मंत्री राज भूषण चौधरी की प्रमुख व्यक्तियों से सौजन्य भेंट: पिंकी कुंडू , के.के. छाबड़ा, अभिषेक राजपूत एवं सुनीता शर्मा रहे सम्मिलित

परिवहन विशेष न्यूज

***नई दिल्ली,** – सरकार, विधिक विशेषज्ञों एवं समुदाय नेताओं के बीच सहयोग को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण आयोजन में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री राज भूषण चौधरी जी ने पिंकी कुंडू जी, के.के. छाबड़ा जी, अभिषेक राजपूत जी एवं सुनीता शर्मा जी जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ सौजन्य भेंट की। इस भेंट में सामाजिक न्याय, जल संसाधन प्रबंधन एवं समुदाय सशक्तिकरण पर साझा दृष्टिकोण पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर प्रतिनिधियों को निषाद समाज की महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित होने का स्वर्णिम अवसर भी प्राप्त हुआ, जो निषाद समुदाय के अधिकारों एवं कल्याण के लिए एक प्रमुख मंच है। चर्चाओं का केंद्र जल सुरक्षा, हाशिए पर पड़े समूहों का सशक्तिकरण एवं सतत विकास पर केंद्रित रहा, जिसमें विधिक पैरवी को नीतिगत पहलों से जोड़ने पर जोर दिया गया।

मानवाधिकार एवं संघर्ष समाधान पर उनके सुझावों ने गहरा प्रभाव छोड़ा, जो मंत्री महोदय की समावेशी शासन प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं।

श्री राज भूषण चौधरी जी ने समूह के योगदान की सराहना करते हुए कहा, ₹ऐसी साझेदारियां नीति को जमीनी हकीकत से जोड़ती हैं, जिससे सभी के लिए समान प्रगति सुनिश्चित होती है।₹ यह आयोजन विधिक बंधु एवं सरकारी निकायों के बीच राष्ट्रीय उत्थान हेतु मजबूत संबंधों का संकेत देता है।

प्रसिद्ध विधिवेत्ता डॉ. अधीश सी. अग्रवाल के नेतृत्व में विश्व शांति हेतु न्यायविदों एवं लेखकों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

शांति एवं न्याय के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पिंकी कुंडू प्रतिष्ठित पुरस्कार से हुईं सम्मानित

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली, 11 मार्च 2026 * – प्रसिद्ध विधिवेत्ता डॉ. अधीश सी. अग्रवाल के नेतृत्व में विश्व शांति हेतु न्यायविदों एवं लेखकों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आज भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र, 40 मैक्स म्यूलर मार्ग पर एक ऐतिहासिक आयोजन के साथ संपन्न हुआ। समारोह का मुख्य आकर्षण यूके एवं यूएस के प्रमुख न्यायाधीशों व वकीलों को सम्मानित करने वाली स्नेहपूर्ण Felicitation Ceremony रही, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून, संघर्ष समाधान एवं मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहा गया।

शाम का सबसे प्रमुख क्षण पिंकी कुंडू जी को शांति एवं न्याय के प्रचार-प्रसार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार का था।

पिंकी कुंडू जी का यह सम्मान नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके अद्वितीय एवं अग्रणी योगदान के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संघर्ष क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों पर अथक पैरवी, विधिक पहलों तथा जमीनी कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है, लैंगिक समानता के लिए बाधाओं को तोड़ा है तथा विधि एवं समाज में नई पीढ़ी की महिला नेतृत्व को प्रेरित किया है। उनका कार्य दर्शाता है कि व्यक्तिगत समर्पण कैसे वैश्विक स्तर पर हाशिए पर पड़ी महिलाओं के लिए प्रणालीगत परिवर्तन ला सकता है।

यह आयोजन संगठन के 2025/2026 के बैंकाक एवं लंदन सम्मेलनों की सफलता पर आधारित था, जहां थाईलैंड-कंबोडिया सीमा विवाद, परमाणु निरस्त्रीकरण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

डॉ. अग्रवाल ने कहा, "बढ़ते संघर्षों के दौर में अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से एकता ही हमारा सबसे मजबूत हथियार है।" समारोह में प्रमुख न्यायविद, लेखक एवं राजनयिक उपस्थित रहे, जो वैश्विक सहयोग को मजबूत करने में इस मंच की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र के प्रतिष्ठित परिवेश ने आयोजन को और गरिमामय बनाया।

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के पदाधिकारियों की दिल्ली सरकार के माननीय श्रम मंत्री कपिल मिश्रा से हुई मुलाकात

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के पदाधिकारियों की दिल्ली सरकार के माननीय श्रम मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी से मुलाकात हुई। यह मुलाकात भारतीय मजदूर संघ, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री डॉ. दीपेंद्र चाहर जी के अथक प्रयासों से संभव हुई।

बैठक के दौरान दिल्ली परिवहन निगम सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

इस अवसर पर दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री भानु भास्कर जी ने विशेष रूप से दिल्ली परिवहन निगम में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों के लिए बेसिक + डीए लागू करने की मांग को प्रमुखता से रखा और कर्मचारियों की अन्य समस्याओं से भी माननीय मंत्री जी को अवगत कराया।

माननीय श्रम मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र ही सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिसमें बेसिक + डीए के विषय को प्रमुखता से लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के प्रभारी श्री बिजेंदर जी, अध्यक्ष श्री गूगन जी, महामंत्री श्री भानु भास्कर जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनोद मलिक जी तथा संगठन मंत्री श्री जयविंदर शेखर जी भी उपस्थित रहे।

भानु भास्कर
महामंत्री
दिल्ली परिवहन मजदूर संघ

पेट्रोलियम संकट से दिल्ली के प्लास्टिक उद्योग पर गहरा असर , कीमतें बढ़ीं

पेट्रोलियम संकट के कारण प्लास्टिक दानों की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, जिससे कपड़े और बिजली के उपकरणों सहित कई उत्पादों की लागत बढ़ने की आशंका है।

नई दिल्ली। युद्ध से पैदा हुए पेट्रोलियम संकट का असर इंडस्ट्री और व्यापार पर भी पड़ने लगा है। पेट्रोलियम से बने प्लास्टिक दानों की कीमत कुछ ही दिनों में दोगुनी हो गई है, जिससे कपड़ों, बिजली के उपकरणों और दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। पेट्रोलियम कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए उद्यमियों ने केंद्र सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की है।

दिल्ली में कितने प्लास्टिक बेस्ड इंडसट्रियल यूनिट ?

दिल्ली में 50,000 से ज्यादा प्लास्टिक बेस्ड इंडसट्रियल यूनिट हैं। उद्यमियों के मुताबिक, प्लास्टिक दाने कई तरह के होते हैं, जिनकी कीमतें हाल के दिनों में 40 से 100 परसेंट तक बढ़ी हैं।

प्लास्टिक एक्सेसरीज़ मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी मुकेश अग्रवाल के मुताबिक, पेट्रोलियम दानों की कीमत उतनी नहीं बढ़ी है, जितनी प्लास्टिक दानों की बढ़ी है। इससे पेट्रोलियम कंपनियों की मनमानी की आशंका बढ़ गई है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि सरकार इस प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत लाए।

पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों पर भी असर

प्लास्टिक दानों का इस्तेमाल कपड़ों, बिजली के उपकरणों, कुर्सियों, घरेलू सामान, पैकेजिंग और कई दूसरे प्रोडक्ट्स में होता है। कीमतों में बढ़ोतरी का असर दूसरे सामानों पर भी पड़ेगा। इसके अलावा, पेट्रोलियम संकट का असर पेंट, वैक्स और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों पर भी पड़ रहा है।

हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर ज़्यादा नहीं है। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन (DHMA) के जनरल सेक्रेटरी श्री भगवान बंसल के मुताबिक, कपड़ों में प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह, कपड़े बनाने में डाई और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। फ्यूल संकट भी है, जिससे कपड़ों की कीमतों में 10 परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार

पिंकी कुंडू

शोरगढ़ की सुबह अभी अंधेरी ही थी, जब जंघावली और बिशम्भरा गाँवों की शांति पुलिस के काफ़िलों की आवाज़ से टूट गई। ठीक सुबह 5 बजे, 13 थानों के 250 से अधिक पुलिसकर्मी पीएसी बल के साथ गाँवों को चारों ओर से घेर चुके थे। इस मिशन का नाम था—ऑपरेशन बजरंग।

नेतृत्व कर रहे थे एसएसपी श्लोक कुमार और एसपी (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत। उनका उद्देश्य स्पष्ट था: उन साइबर अपराध गिरोहों को ध्वस्त करना जिन्होंने इन ग्रामीण इलाकों को डिजिटल धोखाधड़ी का अड्डा बना दिया था और पूरे देश के नागरिकों को निशाना बना रहे थे।

छापेमारी तेज़ी से हुई। दरवाज़े तोड़े गए, संदिग्धों को पकड़ा गया और उपकरण जब्त किए गए। सूरज निकलने तक 34 साइबर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में थे। हालांकि, यह भी साफ़ हो गया कि ये नेटवर्क कितने चालाक हैं—45 आरोपी खेतों के रास्ते भाग निकले।

जब्त किए गए सामान अपराधों की कहानी खुद बयान कर रहे थे: दर्जनों मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड, सिम कार्ड, मोटरसाइकिलें और एक कार—ये सब धोखाधड़ी के औज़ार थे जिनसे फिशिंग कॉल और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे घोटाले किए जाते थे। हर उपकरण एक बड़े धोखाधड़ी नेटवर्क की खिड़की था।

एफआईआर दर्ज हुईं, जांच शुरू हुई और फॉरेंसिक टीमें वित्तीय लेन-देन की कड़ियाँ जोड़ने लगीं। गाँव वालों के लिए इतनी बड़ी पुलिस कार्रवाई का दृश्य चौंकाने वाला भी था और आश्वस्त करने वाला भी—यह संदेश कि कानून व्यवस्था उनके समुदाय को साइबर अपराधियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑपरेशन बजरंग सिर्फ़ एक छापेमारी नहीं था; यह एक घोषणा थी। मथुरा पुलिस ने दिखा दिया कि साइबर अपराध, चाहे वह दूरदराज़ गाँवों में क्यों न जड़ें जमा ले, उसे सटीकता, पैमाने और दृढ़ संकल्प के साथ समाप्त किया जा सकता है। इस अभियान ने नेटवर्क तोड़े, डर पैदा किया और उत्तर प्रदेश में भविष्य की कार्रवाइयों के लिए मिसाल कायम की।

इससे पहले भी, 12 दिसंबर 2025 को मथुरा के देवसिरास गाँव—जिसे "मिनी जामताड़ा" कहा जाता है—में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। वहाँ साइबर अपराधी संगठित तरीके से डिजिटल गिरफ्तारी, फर्जी निवेश और फिशिंग जैसे घोटालों को अंजाम देते थे। उस अभियान में 42 संदिग्ध पकड़े गए थे और यह खुलासा हुआ था कि गाँव साइबर धोखाधड़ी का बड़ा अड्डा बन चुका है।

दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 मार्च को, क्या है नया समय और स्थान?

राजधानी में 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 मार्च को आयोजित की जाएगी। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DSLSA) ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के निर्देश पर यह फैसला लिया है।

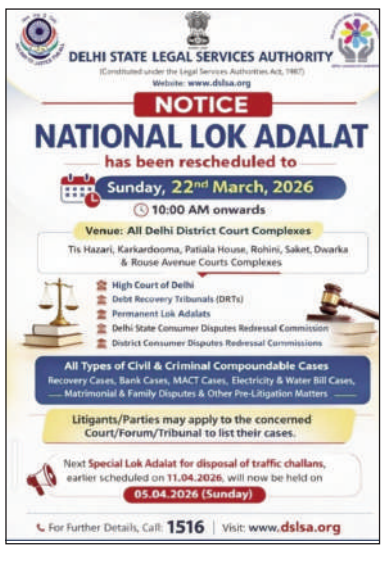

नईदिल्ली। राजधानी में 14 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत को टाल दिया गया है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DSLSA) ने 22 मार्च की नई तारीख तय की है।

DSLSA के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 14 मार्च को हाई कोर्ट के तहत आने वाली सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कोर्ट सिटिंग डे घोषित किया है। इसलिए, DSLSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस वी. कामेश्वर राव के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत को रीशेड्यूल करने का फैसला किया गया।

नेशनल लोक अदालत अब 22 मार्च को तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी। इसमें तलाक के मामलों को छोड़कर, सिविल और क्रिमिनल मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की जाएगी।

नेशनल लोक अदालत सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही नहीं, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, परमानेंट लोक अदालत, दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में भी लगेगी।

DSLSA ने यह भी बताया कि ट्रैफिक चालान के सेटलमेंट के लिए प्रपोज़्ड स्पेशल लोक अदालत की तारीख बदल दी गई है। पहले यह 11 अप्रैल को होनी थी, लेकिन अब यह 5 अप्रैल (रविवार) को होगी।

सिन्धी पंचायत के होली मिलन में गूंजे गीत भजन होली के रसिया सुन झूम उठे सिंधीजन....

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा। सिन्धी जनरल पंचायत का होली मिलन समारोह बहादुर पुरा स्थित स्वामी लीलाशाह धर्मशाला में हुआ, जहां होली के रसिया सुन सिंधीजन झूम उठे। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को फूलों की बौछार कर होली की शुभकामनाएं दी। मंगलवार देर शाम तक चले कार्यक्रम में गीत भजन सहित हर प्रस्तुति पर लगातार तालियां बजती रही।

मीडिया प्रभारी किशोर इसरानी ने बताया कि लगातार 20 दिन चलने वाले सिंधी उत्सव चेटीचंड महोत्सव की शुरूआत होली मिलन से हो गई है, इसी के साथ 20 मार्च तक शहर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

होली मिलन समारोह में एक से बढ़कर एक लोकगीत सुनाए गए। होली की होली संग रसिया में मंत्रमुग्ध भगवान झूलेलाल के अनुयायी सिंधीजन झूमते नाचते रहे। भक्ति संगीत संग फूलों की बौछार के बीच सिंधीजन भक्ति और आनंद में सराबोर हो गए। होली के रसिया में सभी भावविभोर दिखे।

अध्यक्ष नारायण दास लखवानी ने होली को आपसी मेलजोल बढ़ाने वाला त्योहार बताया। मुख्य संयोजक रामचंद्र खत्री ने आगामी होने वाले सिंधी उत्सवों में भागीदारी करके सिंधीयत कायम रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को स्वामी लीलाशाह जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। 16 मार्च को सिंधी नवयुवक मंडल के सौजन्य से नगर में द्वपहिया वाहन रैली में उत्साहपूर्वक भागीदारी करें। पंडित मोहन महाराज ने भगवान झूलेलाल की स्तुति कराई।

इस मौके पर सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष नारायणदास लखवानी, मुख्य संयोजक रामचंद्र खत्री, महामंत्री बसंतलाल मंगलानी, तुलसीदास गंगवानी, जीवतराम चन्दानी, डा. प्रदीप उकरानी, कन्हैयालाल भाईजी, गुरुमुखदास गंगवानी, सुरेशचन्द मेठवानी, जितेन्द्र लालवानी, भगवानदास मंगवानी बेबूभाई, रमेश नाथानी, जितेन्द्र भाटिया, पीताम्बरदास रोहेरा, झामनदास नाथानी, चन्दनलाल आडवानी, सुदामालाल खत्री, हरीश चावला, अशोक अंदानी, गिरधारीलाल नायानी, महेश घावरी, दौलतराम खत्री कन्हैयालाल खत्री एडवोकेट, सुरेश मनसुखानी, विष्णु हेमानी, अनिल मंगलानी, मुकेश मिचुं कोतकवानी, तरुण लखवानी, मन्नू मंगलानी, लक्ष्मणदास वाधवानी, अशोक डाबरा, अमित आसवानी, राजेश कुमार खत्री, वासुदेव खत्री, बंटी खत्री, विशनदास दुपट्टे वाले आदि ने सभी को होली पर्व की बधाई प्रेषित की।

फूहड़ कंटेंट, सोशल मीडिया और संस्कृति: जिम्मेदारी किसकी?

- डॉ. प्रियंका सौरभ

डिजिटल युग ने हमारे समाज की संरचना, सोच और अभिव्यक्ति के तरीकों को गहराई से बदल दिया है। आज मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया है—जहां पहले मनोरंजन और प्रसिद्धि के अवसर सीमित लोगों तक होते थे, वहीं अब हर व्यक्ति के पास अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच है। लेकिन इस नए अवसर के साथ कई नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी बहस उस कंटेंट को लेकर है जिसे समाज का एक वर्ग "फूहड़" या "अशोभनीय" मानता है।

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो तेजी से वायरल होते देखे गए हैं जिनमें डांस, अभिनय या मनोरंजन के नाम पर ऐसे हाव-भाव और प्रस्तुति दिखाई जाती है जिन्हें कई लोग सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध मानते हैं। इन वीडियो को लाखों व्यूज, लाइक्स और शेयर मिलते हैं, जिससे वे और अधिक लोगों तक पहुंचते हैं। लोकप्रियता की इस दौड़ में कई बार कंटेंट की गुणवत्ता और सामाजिक जिम्मेदारी पीछे छूट जाती है।

समाज के एक बड़े वर्ग का मानना है कि इस प्रकार के कंटेंट का प्रभाव विशेष रूप से युवाओं और किशोरों पर पड़ता है। जब वे देखते हैं कि कुछ लोग केवल कुछ सेकंड के वीडियो बनाकर अत्यधिक प्रसिद्धि और आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके मन में भी वैसा ही करने की इच्छा पैदा हो सकती है। कई बार यह प्रेरणा रचनात्मक दिशा में जाती है—जैसे संगीत, कला, नृत्य या शिक्षा से जुड़े कंटेंट बनाना। लेकिन कई मामलों में यह प्रेरणा केवल वायरल होने की दौड़ में बदल जाती है, जहां ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार का तरीका अपनाया जाता है।

यह भी देखा गया है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड और एल्गोरिद्म का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो कंटेंट अधिक देखा और साझा किया जाता है, वही तेजी से फैलता है। ऐसे में यदि दर्शक बार-बार उसी प्रकार के वीडियो देखते हैं जिन्हें वे स्वयं "फूहड़" कहते हैं, तो अनजाने में वे उसी प्रवृत्ति को बढ़ावा भी दे रहे होते हैं। इसलिए केवल कंटेंट बनाने वालों को दोष देना इस समस्या का पूरा समाधान नहीं है। दर्शक भी इस डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

दूसरी ओर, यह तर्क भी सामने आता है कि कला और मनोरंजन की अपनी स्वतंत्रता होती है। नृत्य, अभिनय और अभिव्यक्ति के कई रूप होते हैं, और हर व्यक्ति उन्हें अलग-अलग तरीके से देखता है। जो एक व्यक्ति को अनुचित लगता है, वही दूसरे के लिए केवल मनोरंजन या कला का एक रूप हो सकता है। इसी कारण इस विषय पर समाज में तीखी बहस देखने को मिलती है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण के रूप में देखते हैं।

यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है—क्या किसी भी प्रकार की लोकप्रियता को सफलता का मानक माना जाना चाहिए? सोशल मीडिया ने प्रसिद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। पहले किसी कलाकार को पहचान पाने में वर्षों लग जाते थे; आज एक वायरल वीडियो किसी को रातों-रात स्टार बना सकता है। लेकिन यह त्वरित प्रसिद्धि कई बार स्थायी नहीं होती और इसके सामाजिक प्रभाव भी जटिल हो सकते हैं।

कई युवा इस भ्रम में पड़ सकते हैं कि केवल विवादास्पद या ध्यान आकर्षित करने वाला कंटेंट ही सफलता का रास्ता है। परिणामस्वरूप वे अपनी प्रतिभा को विकसित करने की बजाय तात्कालिक लोकप्रियता के पीछे भागने लगते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती है, बल्कि समाज में मनोरंजन की गुणवत्ता पर भी असर डालती है।

गणपति क्लासिक सोसाइटी में चुनाव को लेकर विवाद, निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार से की शिकायत

गणपति क्लासिक रेजिडेंट्स के निवासी एक सुर में बोलें - सोसाइटी के चुनाव किसी गजटेड अधिकारी की निगरानी में कराए जाएं ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।

साथ ही, पूर्व की कार्यकारिणी समितियों के वित्तीय लेन-देन का ऑडिट कराकर सोसाइटी के धन का पूरा हिसाब भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

निवासियों का कहना है कि वे सोसाइटी में पारदर्शी और लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं तथा इसके लिए वे प्रशासन से निष्पक्ष हस्तक्षेप की अपेक्षा कर रहे हैं।

निवासियों का आरोप है कि वर्तमान कार्यवाहक समिति ने अपने स्वार्थ और मनमानी के लिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया - इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

आगरा। सिकंदरा स्थित गणपति क्लासिक रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी में आगामी कार्यकारिणी चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोसाइटी के कई निवासियों ने वर्तमान कार्यवाहक प्रबंध समिति पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने और चुनाव समिति को अचानक भंग करने का गंभीर आरोप लगाते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स से शिकायत की है।

निवासियों द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, गणपति क्लासिक रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी (पंजीकरण संख्या 40/2018-19, पत्रावली संख्या AG-69569) में हर वर्ष उपविधियों के अनुसार पांच पदाधिकारियों का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जाता है। सोसाइटी में कुल लगभग 274 फ्लैट हैं, जिनमें से 168 सदस्य RWA के पंजीकृत सदस्य हैं और वही मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

शिकायत में बताया गया है कि आगामी वर्ष 2026-27 के लिए प्रबंध समिति के चुनाव की घोषणा 8 फरवरी 2026 को की गई थी। इसी दिन आम सभा की सहमति से एक स्वतंत्र चुनाव समिति का गठन भी किया गया था। चुनाव समिति ने नियमानुसार वोटर सूची तैयार की, चुनाव नियमावली जारी की और मतदान की तिथि 22 मार्च 2026 निर्धारित करते हुए इसकी सूचना व्हाट्सएप तथा सोसाइटी के सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दी थी।

चुनाव प्रक्रिया के तहत इच्छुक प्रत्याशियों के लिए 7 मार्च 2026 को नामांकन पत्र सार्वजनिक स्थान पर रखे गए थे, ताकि इच्छुक सदस्य 9 मार्च 2026 को सुबह 9 से 10 बजे के बीच अपना नामांकन जमा कर सकें।

लेकिन निवासियों का आरोप है कि 8 मार्च की शाम को कार्यवाहक सचिव के हस्ताक्षर और मुहर से जारी एक सूचना में अचानक चुनाव समिति को भंग करने की घोषणा कर दी गई। साथ ही, सार्वजनिक स्थान पर रखे गए नामांकन पत्र भी गायब पाए गए, जिसे निवासियों ने गंभीर और आपराधिक कृत्य बताया है। उनका कहना है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे बीच में बाधित नहीं किया जा सकता।

निवासियों का आरोप है कि वर्तमान कार्यवाहक समिति ने अपने स्वार्थ और मनमानी के लिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

शिकायत में यह भी मांग की गई है कि सोसाइटी के चुनाव किसी गजटेड अधिकारी की निगरानी में कराए जाएं ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। साथ ही, पूर्व की कार्यकारिणी समितियों के वित्तीय लेन-देन का ऑडिट कराकर सोसाइटी के धन का पूरा हिसाब भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

विासियों का कहना है कि वे सोसाइटी में पारदर्शी और लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं तथा इसके लिए वे प्रशासन से निष्पक्ष हस्तक्षेप की अपेक्षा कर रहे हैं।

चुनाव में वर्तमान गणपति क्लासिक रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी सिकंदरा आगरा की कार्यवाहक कमेटी ने चुनाव आयोग ही भंग कर दिया, जो कि आपराधिक मामला है और अपने रिश्तेदारों और वफादारों से मनमानी प्रक्रिया हेतु एक महीने बाद चुनाव कमेटी निरस्त की। इसकी शिकायत कॉलोनी के निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार, सोसाइटी को की गयी। उन्होंने कहा अब चुनाव गजटेड ऑफिसर की देख रेख में होंगे और पिछली टीमो से मांगा जाएगा पैसे का हिसाब ऑडिट होगा।

डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज आगरा मंडल ने कहा कि निवासियों के हित में गजटेड ऑफिसर की देखरेख में चुनाव कराया जाएगा।

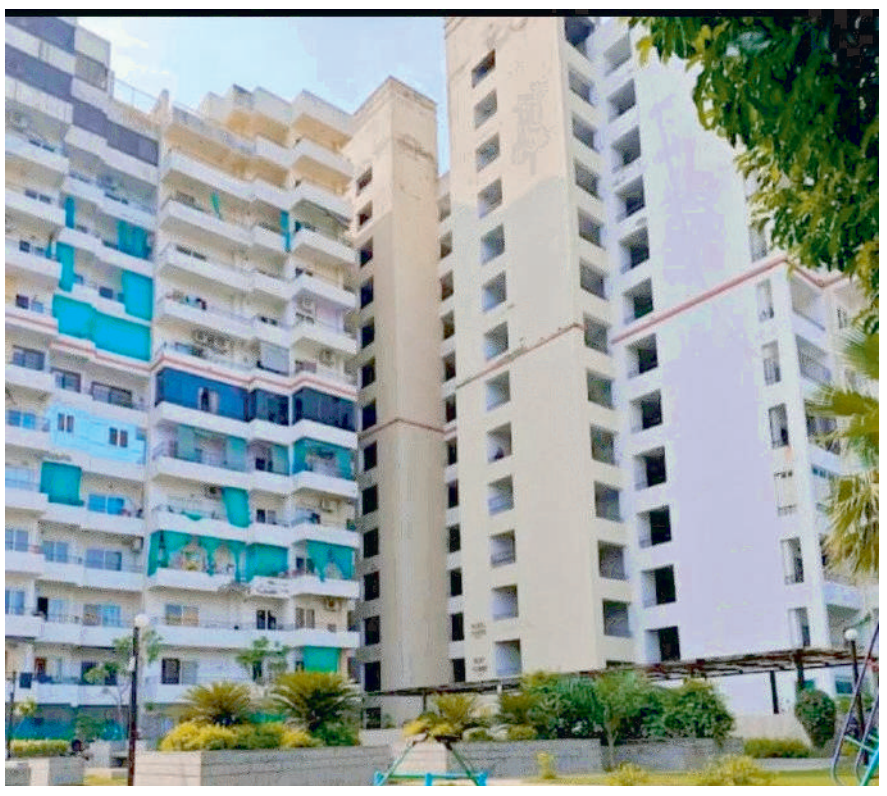

समाधान शिविरों में सुनी जाएंगी आमजन की समस्याएं, मौके पर होगा निपटान

जिला व उपमंडल स्तर पर आज लगाए जाएंगे समाधान शिविर : डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 11 मार्च। जनता की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार 12 मार्च को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे । ये शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगेंगे, जहां नागरिकों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय, झज्जर के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे। इस दौरान उपायुक्त विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सुनेंगे और उपस्थित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश देंगे, ताकि आमजन को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिल सके।

उपमंडल स्तर पर भी संबंधित लघु सचिवालय परिसरों में उपमंडल स्तरीय समाधान शिविर आयोजित होंगे। बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच आईएएस, बेरी में एसडीएम रेणुका नांदल तथा बादली में एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता की अध्यक्षता में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाएगा।

उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि समाधान शिविर प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय में समाधान शिविर प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, ताकि लोगों को एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान मिल सके।

डीसी ने दिए राजस्व कार्यों में पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

विभागवार प्रगति समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

झज्जर, 11 मार्च। जिलाभर में राजस्व विभाग से जुड़ी सेवाओं को लेकर बुधवार को मासिक राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिले के सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा माहवार प्रगति, लंबित कार्यों त्वरित निवारण तथा राजस्व सेवाओं की स्थिति प्रस्तुत की गई। डीआरओ मनबीर सांगवान ने राजस्व संबंधी सेवाओं की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की।

डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने निर्देश दिए कि नामांतरण, ई जमाबंदी, एग्री स्टैक, भू नक्शा, ई रजिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कोर्ट केसों सहित सभी राजस्व सेवाओं का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्वक किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को सुविधाजनक व पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में फील्ड स्तर पर लंबित मामलों, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में गति लाई जाए एवं सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। इस अवसर पर एसडीएम झज्जर अंकित कुमार चौकसे, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, एसडीएम बेरी रेणुका नांदल, एसडीएम बादली डा रमन गुप्ता, डीआरओ मनवीर सिंह सांगवान, डीआईओ अमित बंसल सहित सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

कानपुर में कुकिंग गैस के लिए लाइन में भीड़, काला बाजारी के खिलाफ डीएम की चेतावनी

सुनील बाजपेई

कानपुर। मध्य-पूर्व के देशों में जारी युद्ध के फलस्वरूप कुकिंग गैस की आउटपुट प्रभावित होने से लोग परेशान हैं। यहां बुधवार सुबह गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर सिलेंडर लेने वालों की भीड़ लंबी कतारों में दिखाई पड़ी। लोगों का कहना है कि पहले जहां गैस एजेंसियों पर रोजाना दो गाड़ियां सिलेंडर लेकर आती थीं, वहीं अब दो दिन में मुश्किल से एक गाड़ी पहुंच रही है। जानकारी के मुताबिक यही कारण है कि सप्लाई घटने के कारण एजेंसियों पर सिलेंडर जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। कई उपभोक्ता सुबह से लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। यहां कहीं बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा तो किसी एजेंसी का सर्वर न आने की वजह से बंटने का काम रुका हुआ है। इसके अलावा एजेंसियों में जहां रोज दो गाड़ी आती थी। वहीं, इस समय दो दिन में महज एक गाड़ी पहुंच रही है। सप्लाई घट गई है। यही हाल तहसील बिल्हौर के भी हैं। यहां स्थित एचपी गैस एजेंसी बुधवार सुबह से अब तक बंद पड़ी है। एजेंसी का ताला नहीं खुला और किसी भी कर्मचारी का फोन भी नहीं लग रहा है। एजेंसी के बाहर उपभोक्ता भी नजर नहीं आए, जो भी ग्राहक सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं, ताला बंद देखकर वापस लौट जा रहे हैं। मौके पर मिले कस्बा निवासी संजय त्रिपाठी ने बताया कि वह बुधवार को एजेंसी आए थे, तब कर्मचारियों ने गुरुवार को सिलेंडर देने की बात कही थी।

उन्होंने बताया कि वह गोदाम भी गए थे, जहां कर्मचारियों ने लोड आने के बाद सिलेंडर देने की बात कही है। फिलहाल समस्या के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर यहां के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने चेतावनी दी है कि कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

महिलाएं हर क्षेत्र में कर रही हैं उत्कृष्ट कार्य : डॉ. पद्मिनी सिंह

परिवहन विशेष न्यूज

गाज़ियाबाद। दिल्ली-मेरठ रोड स्थित HLM Group of Institutions में 7 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशासन, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र की कई महिलाओं ने भाग लेकर छात्र-छात्राओं को महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। संस्थान के निदेशक डॉ. अनुज अग्रवाल ने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और शिक्षा के माध्यम से उन्हें और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सीबीआई की डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन एवं विधि एवं न्याय मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. पद्मिनी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने छात्राओं को कानून, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आत्मविश्वास और मेहनत से महिलाएं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया।

इस अवसर पर गाज़ियाबाद जिला जेल की डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में कविता पाठ, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं।

अंत में डॉ. धीरज शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान और समूह फोटो के साथ हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को जारी करेंगे पीएम-किसान की 22वीं किस्त; 9.32 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ

संगिनी घोष

प्रधानमंत्री Narendra Modi 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस संबंध में जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने दी।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इस किस्त के तहत देशभर के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए ₹18,640 करोड़ से अधिक राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होती है।

सरकार के अनुसार Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi देश की सबसे बड़ी किसान आय-सहायता योजनाओं में से एक बन चुकी है। 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही इस योजना के तहत किसानों को हस्तांतरित कुल राशि ₹4.27 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगी।

मंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना से महिला किसानों और छोटे जोतधारकों को विशेष रूप से लाभ मिला है। 22वीं किस्त में 2.15 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को सहायता मिलने की संभावना है, जो कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

ऐसे देखें तो, पीएम-किसान योजना किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्य बिंदु

* प्रधानमंत्री Narendra Modi 13 मार्च को पीएम-किसान की 22वीं किस्त जारी करेंगे
* 9.32 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित
* ₹18,640 करोड़ से अधिक राशि DBT के माध्यम से किसानों के खातों में जाएगी
* Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi के तहत कुल हस्तांतरण ₹4.27 लाख करोड़ से अधिक होगा
* 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को मिलेगा लाभ
* योजना किसानों को सीधी आय सहायता प्रदान करती है

SEO Meta Description:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को पीएम-किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़ से अधिक राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी।

आकाश के परिवार को 12 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की

परिवहन विशेष न्यूज

गोरखपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के सचिव डॉ. वाई सिंह के नेतृत्व में आईएमए का एक प्रतिनिधिमंडल सड़क दुर्घटना में असामयिक रूप से दिवंगत हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के छात्र आकाश के पैतृक गांव बरगदवा माफी, जनपद संत कबीर नगर पहुंचा।

प्रतिनिधिमंडल ने आकाश के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की तथा उनके पिताजी को सांत्वना दी। इस अवसर पर आईएमए गोरखपुर की ओर से 12 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक परिवार को प्रदान किया गया।

आईएमए सचिव डॉ. वाई सिंह ने कहा कि इस कठिन समय में पूरा चिकित्सक समाज आकाश के परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्याय की लड़ाई में आईएमए हर स्तर पर परिवार का सहयोग करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आकाश के परिवार को भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आईएमए से जुड़े चिकित्सकों द्वारा हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा निःशुल्क अथवा रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिनिधिमंडल में सचिव डॉ. वाई सिंह के अतिरिक्त सह सचिव डॉ. दिनेश चंद्र एवं सह सचिव डॉ. अमरेश सिंह भी उपस्थित रहे।

हांसी शहर में अब नहीं दिखाई देंगे खुले कचरा पॉइंट, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की करीब 12 करोड़ की परियोजना शुरू

विधायक विनोद भयाना ने टिपरों को हरी झंडी दिखाकर किया परियोजना का शुभारंभ

हरियाणा/हिसार (राजेशसलूजा): शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हांसी में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की 12 करोड़ की परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना का शुभारंभ विधायक विनोद भयाना ने करीबन एक दर्जन टिपरों को हरी झंडी दिखाकर किया। इस पहल के शुरू होने से अब शहर में खुले कचरा पॉइंट दिखाई नहीं देंगे और घरों तथा दुकानों से ही कचरा एकत्रित किया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक विनोद भयाना ने कहा कि शहर को साफ-सुथरा रखना नगर परिषद और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था शुरू होने से लोगों को अब इधर-उधर कचरा फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे कचरे को इधर-उधर न फेंकें, क्योंकि अब उनके घरों से ही कचरा उठाकर निर्धारित स्थान पर डलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर शहर को गंदा नहीं होने दिया जाएगा।

विधायक ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो लोग अवैध रूप से कचरा पॉइंट बना रहे हैं उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था घरों के साथ-साथ दुकानों के बाहर से भी कचरा उठाने के लिए लागू की गई है।

विधायक विनोद भयाना ने बताया गया कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य पांच वर्षों के लिए राधा कृष्ण कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को ठेके पर दिया गया है। नगर परिषद द्वारा इस कार्य के लिए समिति को प्रति माह करीब 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा, जबकि पांच वर्षों के लिए करीब 12 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है।

समिति द्वारा कचरा कलेक्शन के लिए 30 ऑटो टिपर, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली, एक लोडर, ड्राइवर और पर्याप्त सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल शुरुआत में शहर में 10 ऑटो टिपर, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक लोडर की व्यवस्था की गई है। सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है और इनकी निगरानी एसडब्लूएम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

समिति द्वारा शहरवासियों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों को कचरे के सही प्रबंधन और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे।

उन्होंने बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक कचरा कलेक्शन वाहन की व्यवस्था की रहेगी, जबकि बड़े वार्डों में आवश्यकता के अनुसार दो से तीन वाहनों की व्यवस्था भी की जा सकती है।

इस अवसर पर एसडीएम राजेश खोथ, नगर परिषद के ईओ राजेंद्र सोनी, नगर परिषद के प्रधान प्रवीण इलाहाबादी, पार्षद बलवान सिंह, पार्षद मुकेश टुटेजा, पार्षद विनोद सिंगला, मार्केट कमेटी के उपप्रधान सुरजीत गुर्जर, गोलू चावला, सेनेटरी इंस्पेक्टर संजय सिंह, पार्षद सुभाष, ब्लॉक समिति प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

बुद्धा पार्क को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की महत्वपूर्ण पहल, भारतीय जाटव समाज ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

यह परियोजना मुख्यमंत्रीजी का एक महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके पूर्ण होने से आगरा को एक नई अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी : उपेंद्र सिंह

आगरा,संजय सिंह। कालिंदी विहार रोड पर निर्माणाधीन बुद्धा पार्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने और उसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की मांग को लेकर भारतीय जाटव समाज संस्था के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम आगरा मंडल के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संस्था ने पार्क के निर्माण में ऐतिहासिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता उपेन्द्र सिंह ने बताया कि 3 अगस्त 2025 को संगठन की ओर से लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से आगरा में एक भव्य बुद्धा पार्क के निर्माण का अनुरोध किया गया था, जिसे महाराज जी ने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का एक महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके पूर्ण होने से आगरा को एक नई अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

श्री सिंह ने आगे बताया कि पार्क में गौतम बुद्ध तथा उनके प्रथम पाँच अनुयायियों की भव्य एवं आकर्षण प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। जिस स्थान पर इन प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है, वहां नगर निगम के ठेकेदार द्वारा जेट ब्लैक (गहरे काले रंग) के पत्थर लगाए जा रहे हैं। संस्था ने सुझाव दिया कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लाल अथवा हल्के रंग के पत्थरों के उपयोग पर भी विचार किया जाए, जिससे पार्क की भव्यता और आकर्षण और अधिक बढ़ सके।

संस्था ने पार्क की ऊंचाई और संरचना को देखते हुए सुरक्षा और सौंदर्य के सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की भी आवश्यकता बताई, ताकि यह परियोजना भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन और आध्यात्मिक केंद्र बन सके।

इसके साथ ही संगठन ने विशाल प्रतिमाओं के स्वरूप को ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप बनाए रखने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। संस्था का कहना है कि तथागत बुद्ध को युवा स्वरूप में तथा उनके अनुयायियों को प्रौढ़ स्वरूप में दर्शाया जाना ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना जाता है। साथ ही अनुयायियों के केश विन्यास को भी बुद्ध से भिन्न रखने की बात कही गई है।

संस्था ने इस महत्वपूर्ण परियोजना की गुणवत्ता और ऐतिहासिक स्वरूप बनाए रखने के लिए एक निगरानी समिति के गठन की मांग भी की, जिसमें संगठन को प्रतिनिधित्व दिए जाने का आग्रह किया गया है, ताकि कार्य परंपरा और मानकों के अनुरूप पूरा हो सके और बुद्धा पार्क आगरा की वैश्विक पहचान बन सके।

इस संबंध में संस्था के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल से भी विस्तृत चर्चा की। नगर आयुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर बुद्धा पार्क से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और संस्था के सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर निगम की टीम संस्था के प्रतिनिधियों के साथ मौके पर निरीक्षण करेगी और प्राप्त सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उचित अमल किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में उपेन्द्र सिंह, नेत्रपाल सिंह, भारत सिंह, अर्जुन सिंह, रविन्द्र सिंह, तेज कपूर, रामहेत, प्रेमचंद सोन, सुरेंद्र जाटव, सौरभ वर्मा और वीरपाल सिंह सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा सरकार की तीर्थ स्थलों की निशुल्क दर्शन योजना सराहनीय फैसला : सुरेश गोयल

हरियाणा/हिसार (राजेश सलूजा) : भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री सुरेश गोयल धूप वाला ने हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई निशुल्क तीर्थ दर्शन योजना का स्वागत करते हुए इसे अत्यंत सराहनीय और जनहितकारी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार आय सीमा के आधार पर पात्र वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा निःशुल्क करवाएगी, जिससे समाज के उन वर्गों को भी तीर्थ दर्शन का अवसर मिलेगा जो आर्थिक कारणों से यात्रा करने में सक्षम नहीं होते। सुरेश गोयल ने अपने बयान में कहा कि इससे पहले भी प्रदेश सरकार द्वारा वॉल्वो बस सेवा के माध्यम से तीर्थ यात्राएं करवाई गई थीं, जिनका बड़ी संख्या में बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। अब आईआरसीटीसी के साथ हुए समझौते के तहत हरियाणा से अयोध्या, वाराणसी, पटना साहिब, नांदेड़ साहिब, पुष्कर जी, वैष्णो देवी, शिर्डी और सिंगनापुर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में तीर्थाटन का विशेष महत्व है। तीर्थ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति, मानसिक संतुलन और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करती है। इस प्रकार की योजनाएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना को भी मजबूत करती हैं। सुरेश गोयल ने सुझाव दिया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए दानपात्र की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिसमें इच्छुक यात्री स्वेच्छा से दान कर सकें। इससे यात्रियों में आत्मसंतोष और स्वाभिमान की भावना बनी रहेगी तथा योजना के प्रति उनका भावनात्मक और समर्पण जुड़ाव भी बढ़ेगा। उनमे यह भाव भी जगेगा की हमने मुफ्त तीर्थयात्रा नहीं की हैं।

जगद्गुर श्रीमद् वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी डॉ. वागीश कुमार महाराज की षष्ठीपूर्ति के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय महामनोरथ समारोह 13 मार्च से

14 मार्च को पाञ्चजन्य प्रेक्षागृह में आयोजित होगा वृहद अभिवादन समारोह

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

मथुरा। विश्वविख्यात द्वारकाधीश मन्दिर में श्रीराजाधिराज मंदिर एवं षष्ठीपूर्ति महोत्सव कमेटी, मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में अनंत विभूषित जगद्गुर श्रीमद् वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत तृतीय पीठाधीश्वर परम पूज्य गोस्वामी 108 डॉक्टर वागीश कुमार महाराज की षष्ठीपूर्ति (60वां अवतरण दिवस) के उपलक्ष में त्रि-दिवसीय महामनोरथ समारोह 13 से 15 मार्च 2026 पर्यंत विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य अत्यंत श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है। महोत्सव के अंतर्गत 13 मार्च को श्रीराजाधिराज ठाकुर द्वारकाधीश मन्दिर में सोने का पलना, नंद महोत्सव, कुनवारा एवं फूलफाग आदि के कार्यक्रम आयोजित होंगे।

14 मार्च को पाञ्चजन्य प्रेक्षागृह (भगत सिंह पार्क के पीछे, राजकीय संग्रहालय और मल्टीलेवल पार्किंग के मध्य) डेम्पियर नगर, मथुरा में अपराह्न 03:30 बजे से वृहद अभिवादन समारोह आयोजित होगा।साथ ही पूज्य महाराजश्री के वाचनामृत होंगे। 15 मार्च को प्रातः 08:00 बजे से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।साथ ही दिव्य चुनरी मनोरथ किया जाएगा।इसके अलावा अपराह्न 03:00 बजे से ठाकुरश्री द्वारकाधीश महाराज को अलौकिक छप्पन भोग निवेदित किए जाएंगे। इस दिव्य महामानोरथ समारोह में कांकरोली युवराज गोस्वामी वेदान्त कुमार महोदयश्री एवं युवराज गोस्वामी सिध्धांत कुमार महोदयश्री के अलावा कई प्रख्यात संत, विद्वान, धर्माचार्य, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी व गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ देश-विदेश के असंख्य भक्त-श्रद्धालु भाग लेंगे। महोत्सव के संयोजक डॉक्टर सहदेव कृष्णा चतुर्वेदी, सह-संयोजक राकेश तिवारी, एडवोकेट, अधिकारी वैद्य अशोक कुमार शर्मा, सहायक अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, समाधानीश्री ब्रजेश चतुर्वेदी, समाधानीश्री राजुभाई चतुर्वेदी, शुभमभाई शाह, ध्रुवभाई शाह आदि ने सभी से इस समारोह में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

अब आया स्मार्ट चश्मा: लिखा हुआ पढ़कर सुनाएगा

● डॉ. विजय गर्ग

तकनीक लगातार मानव जीवन को आसान और सुविधाजनक बना रही है। स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब एक नई तकनीक चर्चा में है—स्मार्ट चश्मा। यह ऐसा चश्मा है जो सामने लिखे हुए शब्दों को पहचानकर उन्हें आवाज़ में पढ़कर सुना सकता है। विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों और पढ़ने में कठिनाई महसूस करने वाले व्यक्तियों के लिए यह तकनीक एक बड़ी सहायता साबित हो सकती है।

स्मार्ट चश्मा क्या है

स्मार्ट चश्मा सामान्य चश्मे की तरह दिखता है, लेकिन इसमें छोटे कैमरे, सेंसर, स्पीकर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। यह तकनीक1 ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की मदद से लिखे हुए अक्षरों को पहचानती है और फिर उन्हें आवाज़ में बदल देती है।

इस प्रकार उपयोगकर्ता किताब, अख़बार, बोर्ड या किसी दस्तावेज़ पर लिखी हुई जानकारी को सुन सकता है।

कैसे करता है काम

स्मार्ट चश्मे के फ्रेम में लगा छोटा कैमरा सामने की वस्तु की तस्वीर लेता है। इसके बाद चश्मे में मौजूद प्रोसेसर उस तस्वीर को पढ़कर शब्दों में बदलता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्स्ट-टू-स्पीच तकनीक की मदद से वह शब्दों को आवाज़ के रूप में उपयोगकर्ता को सुनाए जाते हैं।

कुछ उन्नत स्मार्ट चश्मे मोबाइल फोन या इंटरनेट से भी जुड़ सकते हैं, जिससे उनका उपयोग और अधिक सुविधाजनक हो जाता है।

दृष्टिबाधित लोगों के लिए वरदान

यह तकनीक खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। दृष्टिबाधित व्यक्ति अब किताबों, पत्रों, संकेतों और दस्तावेज़ों को दूसरों की मदद के बिना समझ सकते हैं।

्मार्ट चश्मा उन्हें अधिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है। इससे शिक्षा, रोज़मर्रा के काम और सार्वजनिक स्थानों पर जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है।

शिक्षा और समाज में उपयोग

स्मार्ट चश्मे का उपयोग केवल दृष्टिबाधित लोगों तक सीमित नहीं है। विद्यार्थी, शोधकर्ता और व्यस्त पेशेवर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति चलते-फिरते किताब या दस्तावेज़ सुन सकता है।

इसके अलावा यह तकनीक भाषा सीखने, अनुवाद और जानकारी प्राप्त करने के नए अवसर भी प्रदान कर सकती है।

भविष्य की संभावनाएँ

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में स्मार्ट चश्मे और भी उन्नत होंगे। इनमें वस्तुओं की पहचान, चेहरे पहचानने की क्षमता, रास्ता बताने जैसी सुविधाएँ भी जोड़ी जा सकती हैं। कई तकनीकी कंपनियाँ इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिनमें गूगल और मेट जैसी कंपनियाँ शामिल हैं।

निष्कर्ष

स्मार्ट चश्मा आधुनिक तकनीक का एक ऐसा उदाहरण है जो मानव जीवन को अधिक सरल और समावेशी बना सकता है। विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह तकनीक ज्ञान और जानकारी तक पहुँच का एक नया द्वार खोल सकती है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्मार्ट चश्मा केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि तकनीक और मानव संवेदना के मेल का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में शिक्षा और सामाजिक जीवन को नई दिशा दे सकता है।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

पारंपरिक मेलों पर संकट: सुरक्षा और आजीविका के बीच संतुलन की तलाश

जगराम गुर्जर

भारत के पारंपरिक मेले केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं. वे हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का जीवंत हिस्सा हैं। गांव-गांव, शहर-शहर लगने वाले ये मेले सदियों से लोगों के मेल-मिलाप, लोक संस्कृति और आजीविका का आधार रहे हैं। यहां झूले लगाने वाले, खिलौने बेचने वाले, बर्तन, चूड़ी, हस्तशिल्प बेचने वाले दुकानदार, बुनकर, लोक कलाकार और छोटे कुटीर उद्योगों से जुड़े हजारों परिवार अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं लेकिन आज यह पारंपरिक कारोबार गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। विशेष रूप से गुजरात में तो स्थिति ऐसी बन गई है कि मेले लगभग समाप्ति की ओर हैं। अन्य राज्यों में भी कड़े नियमों की आशंका से मेला आयोजकों और झूला संचालकों के बीच असुरक्षा का माहौल है।

राजकोट में एक गेमिंग जोन में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस हादसे के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त नियम लागू किए। जन सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन नियम बनाते समय इस बात पर शायद ध्यान ही नहीं दिया गया कि राजकोट की घटना एक बंद, पक्के और अवैध गेमिंग जोन में हुई थी जबकि पारंपरिक मेले और झूले खुले वातावरण में अस्थायी ढांचे में लगाए जाते हैं। खुले मेलों के झूले न तो पक्के भवनों में होते हैं, न ही उनमें जटिल बिजली व्यवस्था या आग पकड़ने वाली बनावट होती हैं। इसके बावजूद नए नियमों का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं छोटे मेला आयोजकों और झूला संचालकों पर पड़ा है। नए प्रावधानों के तहत महंगे इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, भारी बीमा कवर, जटिल लाइसेंस प्रक्रिया और बार-बार निरीक्षण जैसी शर्तें लागू कर दी गई हैं। छोटे स्तर पर काम करने वाले ये लोग पहले ही भारी कर्ज लेकर अपने झूले खरीदते हैं। उनके लिए महंगे प्रमाण पत्र और बीमा प्रीमियम जुटाना लगभग असंभव है। परिणामस्वरूप, गुजरात में मेले लगने बंद हो गए हैं, झूले खुले मैदानों में जंग खा रहे हैं और हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मेले और झूले वालों में से अधिकांश के पास इस पारंपरिक काम के अलावा कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं है। पीढ़ियों से यही इनका पेशा रहा है। यह केवल व्यवसाय नहीं, इनकी पहचान भी है। यदि यह बंद होता है तो केवल रोजगार ही नहीं, एक जीवंत लोक परंपरा भी समाप्त हो जाएगी।

गौर करने वाली बात है कि कोई भी मेला आयोजक या झूला संचालक सुरक्षा नियमों को हटाने की मांग नहीं कर रहा। बंद गेमिंग जोनों के लिए कठोर नियम आवश्यक हैं और उनका पालन होना चाहिए लेकिन खुले मेलों के पारंपरिक झूलों के लिए अलग, सरल और व्यवहारिक नियम बनाए जाने चाहिए।

सरकार यदि श्रेणीकरण (कैटेगराइजेशन) की व्यवस्था करे तो भी झूले वालों को राहत मिल सकती है। जैसे बड़े यांत्रिक राइड्स और छोटे पारंपरिक झूलों के लिए अलग-अलग मानक बनाए जाएं तो इससे संतुलन बन सकता है। इसके साथ ही समूह बीमा योजना, कम लागत निरीक्षण प्रणाली और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कदम उठाए जाएं तो मेला व्यवसायी सुरक्षा मानकों का पालन भी कर सकेंगे और अपनी आजीविका भी बचा पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए नियमों को लागू करते समय ग्रेस पीरियड दिया जाए। यदि दो से तीन वर्षों का समय दिया जाए तो छोटे संचालक धीरे-धीरे आवश्यक प्रावधानों को पूरा कर सकते हैं। अचानक लागू की गई कठोर शर्तों ने पूरे तंत्र को ठप कर दिया है।

हाल में सूरजकुंड में झूला टूटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी सामने आई। ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से चिंताजनक हैं लेकिन हर हादसे का पूरा दोष झूला संचालक पर डाल देना न्यायसंगत नहीं है। यह भी जांच का विषय है कि कहीं झूलों के निर्माण में तकनीकी खामी या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं था। आज देश में अनेक झूला निर्माता कार्यरत हैं। क्या उनके निर्माण मानकों की नियमित जांच होती है? क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर झूला तकनीकी कसौटियों पर खरा उतरता है?

संपादकीय चिंतन-मनन

विकास के सफर में सूक्ष्मजीव का साथ

डॉ विजय गर्ग

जब हम विकास और प्रगति की बात करते हैं तो अक्सर बड़ी तकनीकों, उद्योगों और वैज्ञानिक खोजों का जिक्र करते हैं। लेकिन इस विकास यात्रा में एक ऐसा अदृश्य साथी भी है, जिसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है—सूक्ष्मजीव। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, फिर भी इनका प्रभाव पृथ्वी के जीवन, पर्यावरण और मानव सभ्यता पर गहरा है।

सूक्ष्मजीव क्या हैं

सूक्ष्मजीव वे जीव होते हैं जो अत्यंत छोटे आकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और कुछ प्रकार के प्रोटोजोआ। ये मिट्टी, पानी, हवा, पौधों और मनुष्य के शरीर तक हर जगह पाए जाते हैं।

हालाँकि कुछ सूक्ष्मजीव बीमारियाँ फैलाते हैं, लेकिन अधिकांश सूक्ष्मजीव मानव जीवन और प्रकृति के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं।

कृषि विकास में भूमिका

कृषि क्षेत्र में सूक्ष्मजीवों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीव पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य रूप में बदल देते हैं।

इसी तरह जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक भी सूक्ष्मजीवों की सहायता से बनाए जाते हैं, जिससे खेती अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल बनती है।

उद्योग और खाद्य उत्पादन

सूक्ष्मजीव खाद्य और औद्योगिक उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दही, पनीर, सिरका और कई प्रकार के किण्वित खाद्य पदार्थ सूक्ष्मजीवों की मदद से बनते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है।

औषधि उद्योग में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। कई प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएँ, एंजाइम और विटामिन सूक्ष्मजीवों की सहायता से तैयार किए जाते हैं।

पर्यावरण संरक्षण में योगदान

पर्यावरण की सफाई और संतुलन बनाए रखने में भी सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मृत पौधों और जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को फिर से प्रकृति में लौटाते हैं। इस प्रक्रिया को जैविक निम्नीकरण कहा जाता है।

आजकल वैज्ञानिक प्रदूषण कम करने के लिए भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर रहे हैं। तेल रिसाव, औद्योगिक कचरे और प्लास्टिक के अपघटन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका पर लगातार शोध चल रहा है।

मानव स्वास्थ्य में भूमिका

मानव शरीर में भी अरबों सूक्ष्मजीव रहते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मानव माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कई शारीरिक प्रक्रियाओं में मदद करते हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि सूक्ष्मजीव केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर भी हमारे सहयोगी हैं।

निष्कर्ष

सूक्ष्मजीव भले ही आँखों से दिखाई न दें, लेकिन विकास और जीवन की पूरी प्रक्रिया में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और पर्यावरण—हर क्षेत्र में सूक्ष्मजीव मानवता के विकास के अदृश्य साथी हैं।

भविष्य में जब विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ेगी, तब सूक्ष्मजीवों के उपयोग से नई खोजें और समाधान सामने आएँगे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव विकास की यात्रा में सूक्ष्मजीव हमारे मौन लेकिन शक्तिशाली सहयोगी हैं।

डॉ विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

पश्चिम एशिया की जंग,मध्य-पूर्व संकट- भारत की रसोई तक पहुँचा-एलपीजी संकट के बीच सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का ब्रह्मास्त्र चलाया-7 साल तक की जेल

पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं
भारत के लिए मौजूदा तेलीय पदार्थ संकट,ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता देश की आर्थिक स्थिरता के संकट की चेतावनी व ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अवसर भी प्रदान करता है -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को एक बार फिर अस्थिर कर दिया है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच टकराव केवल क्षेत्रीय संघर्ष भर नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है।खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण दुनियाँ के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक,स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा उत्पन्न हो गई है। यही मार्ग विश्व के बड़े हिस्से में तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।इस मार्ग में व्यवधान का असर भारत के ईंधन बाजार पर सीधा पड़ा है। एलपीजी टैंकरों के फंस जाने,कच्चे तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने और गैस आपूर्ति में अनिश्चितता के कारण भारत के ऑटो- एलपीजी तथा औद्योगिक गैस बाजार में भारी दबाव पैदा हो गया है,ऐसे में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. नई दरों के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया है।स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को 5 मार्च 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करना पड़ा।सामान्य परिस्थितियों में यह कानून कम ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मौजूदा संकट ने इसे फिर से सक्रिय करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि दरअसल यह संकट केवल ऊर्जा बाजार का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा और आम नागरिकों की दैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआहै।भारत में करोड़ों परिवार रसोई गैस पर निर्भर हैं और औद्योगिक उत्पादन भी ऊर्जा आपूर्ति से सीधे जुड़ा हुआ है ऐसे में पश्चिम एशिया की जंग भारत की रसोई और उद्योग दोनों के लिए सटीक गंभीर चुनौती बनकर सामने आई है।

साथियों बात अगर हम भारत की ऊर्जा निर्भरता:आयात पर आधारित संरचना को समझने की करें तो भारत दुनियाँ की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके साथ-साथ ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन देश की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि घरेलू स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन सीमित है। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है।एलपीजी के मामले में भी स्थिति लगभग यही है। देश में हर साल लगभग 3 करोड़ 13 लाख टन एलपीजी की खपत होती है,जबकि घरेलू उत्पादन करीब 1 करोड़ 28 लाख टन ही है। इसका मतलब है कि लगभग 58 प्रतिशत एलपीजी आयात पर निर्भर है।इस आयात का लगभग 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत तक पहुंचता है। यह वही समुद्री मार्ग है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस का प्रमुख रास्ता माना जाता है।जब इस मार्ग में युद्ध के कारण बाधा आई तो एलपीजी टैंकरों की आवाजाही रुक गई। परिणाम स्वरूप भारत में गैस आपूर्ति की स्थिति अचानक अस्थिर हो गई।सरकार के पास मौजूद बफर स्टॉक के आधार पर देश लगभग 25 से 30 दिन तक एलपीजी की जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन अगर आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहती है तो संकट और भी बहुत गंभीर हो सकता है।

साथियों बात अगर हम कतर की एलएनजी सुविधा पर हमला और आपूर्ति संकट को समझने की करें तो, ऊर्जा संकट को और गहरा करने वाली एक अन्य घटना कतर की एलएनजी सुविधा पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमले थे। कतर दुनियाँ के प्रमुख गैस निर्यातकों में से एक हैऔर भारत के लिए भी एलएनजी का महत्वपूर्ण स्रोत है।हमले में कतर की एलएनजी सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद भारत की कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर से गैस आपूर्ति पर फोर्स मैजर घोषित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अनुबंध होने के बावजूद गैस की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई।इस घटना ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया।एलएनजी और एलपीजी दोनों की आपूर्ति प्रभावित होने लगी, जिससे ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई ऐसी स्थिति में सरकार के सामने दोहरी चुनौती थी एक ओर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और दूसरी ओर बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना।

साथियों बात अगर हम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955: संकट में सरकार का सबसे बड़ा हथियार इसको समझने की करें तो, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू किया। यह कानून भारत में आवश्यक वस्तुओं केउत्पादन वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था।इस अधिनियम के तहत सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी भी जरूरी वस्तु के उत्पादन,स्टॉक,वितरण और कीमतों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित कीमत पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।इस कानून को अक्सर सरकार का "ब्रह्मास्त्र" कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत सरकार को असाधारण अधिकार मिलते हैं। वह कंपनियों और व्यापारियों को निर्देश दे सकती है कि वे कितना उत्पादन करें, कितना स्टॉक रखें और किस कीमत पर बिक्री करें।पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद इस कानून के तहत शुरू से ही शामिल रहे हैं। हालांकि तेल क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। यही कारण है कि 2026 में एलपीजी संकट के दौरान इसका उपयोग एक बड़ा और असामान्य कदम माना जा रहा है।

साथियों बात अगर हम सरकार ने यह कानून क्यों लागू किया? इसको समझने की करें तो सरकार के इस कदम के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं।सबसे पहला कारण गैस आपूर्ति में संभावित रुकावट है। खाड़ी देशों से होने वाली गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा युद्ध के कारण प्रभावित हो गया है। अनुमान है कि भारत को मिलने वाली लगभग 60 प्रतिशत गैस आपूर्ति पर इसका असर पड़ सकता है।दूसरा कारण जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकना है। जब भी बाजार में किसी आवश्यक वस्तु की कमी की आशंका होती है तो कुछ व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए उसका स्टॉक जमा करने लगते हैं। इससे कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं।तीसरा कारण घरेलू उपयोग को प्राथमिकता देना है। सरकार ने रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे गैस घटकों का इस्तेमाल अन्य उत्पादों के बजाय एलपीजी उत्पादन के लिए करें। इससे घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इन सभी कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में गैस की आपूर्ति सामान्य बनी रहे और आम लोगों को संकट का सामना न करना पड़े।

साथियों बात अगर हम एलपीजी उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण को समझने की करें तोआवश्यक वस्तु अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने एलपीजी उत्पादन और वितरण प्रणाली में कई बदलाव किए हैं।रिफाइनरियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने उत्पादन का बड़ा हिस्सा घरेलू एलपीजी जरूरतों को पूरा करने में लगाएं। इसके अलावा व्यापारियों और वितरकों के लिए स्टॉक लिमिट तय की जा सकती है।अगर कोई व्यापारी या कंपनी तय सीमा से अधिक स्टॉक जमाकरती है तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हैइस कानून के तहत अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे गोदामों की जांच करें और जरूरत पड़ने पर स्टॉक जब्त कर लें।इस व्यवस्था का उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना और आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित करना है।आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।इस कानून की धारा 7 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या संस्था जमाखोरी, कालाबाजारी या अवैध व्यापार में शामिल पाई जाती है तो उसे 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।इस सख्त प्रावधान का उद्देश्य यहसुनिश्चित करना है कि बाजार में कोई भी व्यक्ति या संस्था संकट की स्थिति का फायदा उठाकर अनुचित लाभ बिलकुल भी न कमा सके।

साथियों बात अगर हम 2022 के बाद पहली बार इतना बड़ा कदम इसको समझने की करें तो, तेल क्षेत्र में आवश्यक वस्तु अधिनियम का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इससे पहले 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान इसे सीमित रूप से लागू किया गया था।उस समय सरकार ने रिफाइनरियों को निर्यात रोककर घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।लेकिन 2026 में एलपीजी उत्पादन के लिए सीधे निर्देश देना एक असाधारण कदम माना जा रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार ऊर्जा संकट को लेकर गंभीर है और घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है।

साथियों बात अगर हम गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव को समझने की करें तो ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। पहले उपभोक्ता किसी सिलेंडर की डिलीवरी के 21 दिन बाद नया सिलेंडर बुक कर सकते थे,लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है सरकार का कहना है कि यह बदलाव जमाखोरी को रोकने और वितरण प्रणाली को संतुलित बनाए रखने के लिए किया गया है।हालांकि कुछ परिवारों में गैस की खपत अधिक होती है, इसलिए यह चिंता भी सामने आई है कि अगर सिलेंडर 25 दिन से पहले खत्म हो जाए तो क्या होगा ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्प अगर किसी परिवार में गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है तो उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। कई मामलों में एजेंसी विशेष अनुमति देकर जल्दी बुकिंग की सुविधा प्रदान कर सकती है।

इसके अलावा उपभोक्ता अतिरिक्त शुल्क देकर इमरजेंसी सिलेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन परिवारों में गैस की खपत अधिक है उनके लिए डबल सिलेंडर कनेक्शन लेना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।इस व्यवस्था में एक सिलेंडर खत्म होने के बाद दूसरा तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है और इस दौरान नया सिलेंडर बुक करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।

साथियों बात अगर हम ऊर्जा संकट और भारत की दीर्घकालिक रणनीति को समझने की करें तो मौजूदा संकट ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी।सरकार पहले से ही कई कदम उठा रही है। इनमें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना शामिल है।भारत सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर भी तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा जैव ईंधन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।इन सभी प्रयासों का उद्देश्य तेल और गैस आयात पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक राजनीति का नया समीकरण बना है,पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है बल्कि इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है।भारत के लिए यह स्थिति एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी।चेतावनी इसलिए क्योंकि ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता देश की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।अवसर इसलिए क्योंकि यह संकट ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज कदम उठाने का मौका भी देता है।आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग करके सरकार ने फिलहाल गैस संकट को नियंत्रित करने की कोशिश की है।लेकिन दीर्घकालिक समाधान तभी संभव है जब भारत ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाए और घरेलू उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दे। यदि ऐसा किया जाता है तो भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट का प्रभाव भारत की रसोई और उद्योग पर सीमित रहेगा और देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बना

सरेंडर की मांग से भड़का संघर्ष: क्या यह युद्ध लंबा और विनाशकारी होगा?

प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

मध्य पूर्व अचानक संघर्ष की भयंकर आग में झुलस रहा है। 6 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से "पूर्ण और बिना शर्त आत्मसमर्पण" की मांग की — कोई सौदा नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं, सिर्फ पूरी तरह जीत। यह अल्टीमेटम युद्ध के सातवें दिन आया, जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हजारों लक्षित हमले किए। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि केवल आत्मसमर्पण के बाद ही ईरान में नया "महान और स्वीकार्य नेता" चुना जाएगा और देश का पुनर्निर्माण होगा। इस मांग ने कूटनीतिक रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया है। वैश्विक मीडिया इसे "मैक्सिमलिस्ट वॉर ऐम्स" के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिससे साफ है कि यह संघर्ष लंबे समय तक जारी रह सकता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज़तबा खामेनेई ने इसे केवल एक "सपना" करार देते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया, जिससे तनाव और भी गहरा गया है।

खामेनेई के कड़े शब्दों ने अमेरिका के लिए सीधे चुनौती खड़ी कर दी। ईरान ने ट्रंप का अल्टीमेटम ठुकराते हुए कहा, "हम अंत तक लड़ेंगे।" इसके तुरंत बाद, ईरानी मल्टी-वारहेड मिसाइलों ने इज़राइल और गल्फ क्षेत्रों को विनाश की आग में ढक दिया। 10 मार्च तक, युद्ध के 11वें दिन, 140 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जिनमें 8 की स्थिति गंभीर है। पेंटागन चुप्प है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ इसे "साइलेंट किलर" मोड कहते हैं। ईरान ने क्षेत्रीय सहयोगियों को सक्रिय किया, जिससे लेबनान में 10 लाख लोग विस्थापित हुए। यह संघर्ष अब एट्रिशन वार की ओर बढ़ रहा है, जहां कोई स्पष्ट विजेता दिखाई नहीं देता। ट्रंप का दावा कि ईरान की मिसाइल क्षमता 80% कम हो गई है, हकीकत से मेल नहीं खाता, क्योंकि जवाबी हमले लगातार जारी हैं। रूस के साथ ईरान की बातचीत अमेरिकी आर्थिक दबाव को और गहरा रही है।

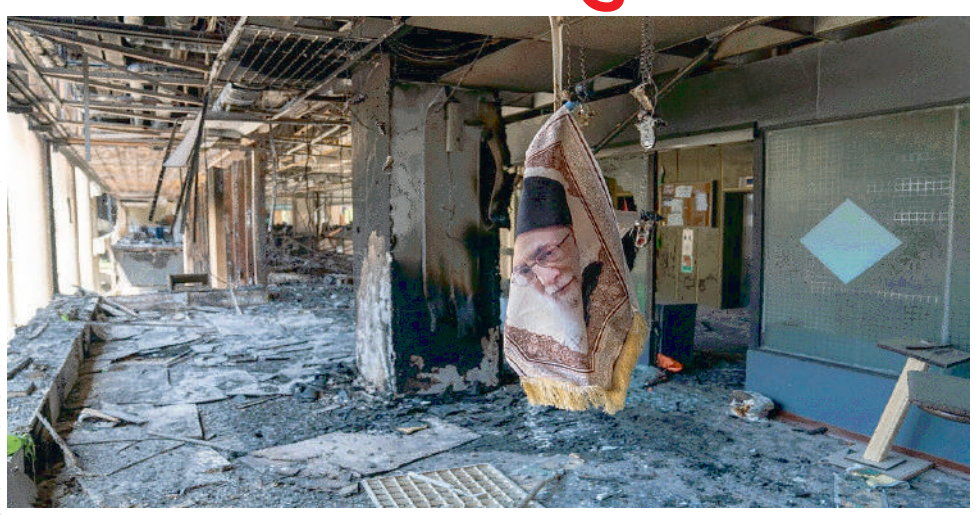

वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट की कगार पर खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे "मेजर ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी" घोषित किया। अब तक 1000 से अधिक नागरिक स्थल तबाह हो चुके हैं। मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल रही है, बेरूत से तेहरान तक बमबारी जारी है। तेल की कीमतें 91 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई हैं और होर्मुज स्ट्रेट में खतरे के कारण और बढ़ सकती हैं। जर्मन चांसलर ने चेतावनी दी कि बिना ठोस एग्जिट प्लान के युद्ध अनंत तक खिंच सकता है। चीन ने ईरान को स्पष्ट संदेश दिया कि अमेरिका और इजराइल को चुनौती न दें, जबकि रूस का समर्थन ईरान को जारी है। ट्रंप बार-बार "विजय नजदीक" बता रहे हैं, लेकिन मिसाइल हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। दुनिया की निगाहें थम गई हैं, क्योंकि किसी भी क्षण परमाणु खतरे का भय मंडरा रहा है।

भारत की ऊर्जा व्यवस्था संकट के सबसे गंभीर मोड़ पर है। देश का लगभग 50-60% तेल होर्मुज स्ट्रेट से आता है, जो किसी भी समय पूरी तरह बंद हो सकता है और आपूर्ति ठप्प कर सकता है। पेट्रोल और डीजल 200 रुपये पार कर सकते हैं, जबकि एलपीजी की कमी घरेलू अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल रही है। हवाई यात्रा ठप हो गई, फ्लाइट्स 14 घंटे तक फंसीं और लाखों लोग प्रभावित हुए। फरवरी 2026 में आयातित तेल की मात्रा देश की कुल जरूरत का 53% थी, और अब वैकल्पिक स्रोतों की ओर नजरें गड़ाई गई हैं—रूस, अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका ही संभावित विकल्प बन रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दबाव और शांति के बीच संतुलन साधना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बैकचैनल्स के जरिए शांति के संकेत भेजे जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटम से पीछे हटना लगभग असंभव है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बिना रिजीम चेंज के कोई "जादुई जीत" संभव नहीं। ईरान ने सरेंडर नहीं किया; उसका नेतृत्व और भी रेडिकल हो गया है। अमेरिकी बलों ने अब तक 5000 से अधिक टारगेट्स हिट किए, लेकिन ईरानी मिसाइलें लगातार जारी हैं। पेंटागन की चुप्पी वैश्विक स्तर पर सवाल खड़े कर रही है और यह अल्टीमेटम युद्ध को लंबा खींच सकता है, जिससे आर्थिक भार अमेरिका पर भारी पड़ेगा।

ईरान पूरी तरह अमेरिका को थकाने और दबाव में रखने की रणनीति पर केंद्रित है। होर्मुज स्ट्रेट और प्रमुख तेल पाइपलाइंस को निशाना बनाकर उसने वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ा दिया है। क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के लिए विद्रोही समूहों को सक्रिय करना उसकी रणनीति का हिस्सा बन गया है। युद्ध का कोई सुरक्षित ऑफ-रैंप न होने के कारण यह दावा कि यह जल्द खत्म होगा पूरी तरह खोखला लगता है। संघर्ष का प्रभाव अब खेलों और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों तक पहुँच गया है—भारतीय महिला फुटबॉल टीम के वीजा अटक गए, जबकि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हफ्तों तक फंसे रहे, कुछ खिलाड़ी कमर्शियल फ्लाइट्स से 9-10 दिन बाद घर लौट पाए, जिससे खेल जगत गहरे संकट में है।

डिप्लोमेसी अब सबसे अहम जरूरत बन गई है। रूस और ईरान की बातचीत जारी है, जबकि चीन की चेतावनी स्पष्ट और सख्त है। ट्रंप बैकचैनल्स के माध्यम से शांति के संकेत दे रहे हैं, लेकिन "सरेंडर या डाई" अल्टीमेटम इसे रोक रहा है। ईरान न्यूक्लियर रिफाइनमेंट तेज कर सकता है, जो वैश्विक स्तर पर बड़ा खतरा पैदा करता है। अब दुनिया के नेताओं को तुरंत मध्यस्थता करनी होगी, वरना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और गहरा जाएगा। यह अल्टीमेटम इतिहास में दर्ज होगा—या तो अमेरिकी "विजय" के रूप में, या गंभीर भूल के रूप में।

भविष्य की अनिश्चितता ने पूरी दुनिया को गहरी चिंता में डाल दिया है। यदि ईरान पीछे नहीं हटता, तो यह संघर्ष लंबे एट्रिशन युद्ध में बदल सकता है—जहाँ मौतों की संख्या बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ट्रंप को अपना अल्टीमेटम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, और घोषित "विक्ट्री" केवल राजनीतिक बयान भर रह जाएगी। दूसरी ओर, ईरान अपने सहयोगियों के साथ अंत तक लड़ने का संकेत दे चुका है। भारत जैसे देश तटस्थ रहते हुए कूटनीति के रास्ते को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यह अल्टीमेटम शांति की संभावनाओं को कठिन परीक्षा में डाल रहा है। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि ट्रंप की दिखावटी ताकत भारी पड़ेगी या ईरान की दृढ़ता पूरी दुनिया को एक नए संकट के दौर में धकेल देगी।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय: दांडी मार्च-12 मार्च 1930

-सुनील कुमार महला

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से 12 मार्च 1930 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। जैसा कि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक लगभग 390 किलोमीटर (241 मील) की ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू की थी। गौरतलब है कि इस आंदोलन को दांडी मार्च, नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह कहा जाता है। वास्तव में, यह ब्रिटिश/अंग्रेजी सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून के खिलाफ किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था।

आंदोलन की शुरुआत:-

इस यात्रा में शुरुआत में केवल 78 सत्याग्रही शामिल थे (कुछ स्रोतों में 79 का भी उल्लेख मिलता है), लेकिन रास्ते में हजारों लोग इस आंदोलन से जुड़ते गए। गांधीजी की आयु उस समय 61 वर्ष थी, फिर भी वे 24 दिनों तक प्रतिदिन लगभग 16 से 19 किलोमीटर पैदल चलते रहे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गांधीजी के मार्च शुरू करने से पहले ही उनके प्रमुख सहयोगी और रणनीतिकार सरदार वल्लभभाई पटेल को 7 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल, अंग्रेजी सरकार को यह आशंका थी कि पटेल की संगठनात्मक क्षमता इस आंदोलन को और भी व्यापक बना सकती है।

नमक को आंदोलन का प्रतीक क्यों बनाया गया ?

नमक को इस आंदोलन का प्रतीक बनाया गया क्यों कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन और उसकी बिक्री पर जहां एक ओर कर (टैक्स) लगा रखा था वहीं पर दूसरी ओर उस पर एकाधिकार (मोनोपॉली) भी था।नमक आम जन की रोजमर्रा जिंदगी का अहम्हिस्सा था और आम जनता को नमक के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, जो कभी-कभी उसके वास्तविक मूल्य से 14 गुना तक अधिक हो जाती थी। जानकारी तो यह भी मिलती है कि सरकार उस नमक को भी नष्ट कर देती थी, जिसे वह ऊंचे दाम पर बेच नहीं पाती थी, ताकि लोग उसे मुफ्त में न उठा सकें। गांधीजी ने नमक को आंदोलन का प्रतीक इसलिए चुना, क्योंकि नमक हर गरीब-अमीर की दैनिक आवश्यकता है। इस साधारण विषय के माध्यम से उन्होंने पूरे देश की जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। हालांकि, शुरुआत में कांग्रेस के कुछ नेताओं को यह मुद्दा बहुत ही छोटा लगा और उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में यही आंदोलन पूरे देश में फैल गया।

दांडी पहुँचकर कानून भंग:-

इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधीजी गुजरात के तटीय गांव दांडी पहुँचे। वहां उन्होंने समुद्र तट पर पड़ी नमक-मिश्रित मिट्टी उठाकर ब्रिटिश नमक कानून का सांकेतिक रूप से उल्लंघन किया। वास्तव में उन्होंने नमक बनाया नहीं था, बल्कि मिट्टी और नमक के मिश्रण को उठाकर कानून तोड़ा था। पाठकों को बताता चलूं कि दांडी में गांधीजी द्वारा बनाए गए चुटकी भर नमक की उस समय नीलामी हुई, जो 1600 रुपये में बिका था। आज के मूल्य के अनुसार यह राशि लाखों रुपये के बराबर मानी जाती है।

दांडी आंदोलन का विस्तार:-

दांडी मार्च के बाद पूरे देश में नमक कानून तोड़ने की जैसे लहर-सी फैल गई थी। लाखों लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। यह भी उल्लेखनीय है कि 5 मई 1930 को गांधीजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी यह आंदोलन जारी रहा। बाद में कवयित्री और महान्-स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को लगभग 2500 सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हुए बंबई से लगभग 150 मील उत्तर स्थित धरासना नमक कारखाने पर सत्याग्रह किया।

दांडी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव:-

दांडी मार्च को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर की बड़ी व महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने धरासना सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रहियों पर हुए पुलिस के क्रूर लाठीचार्ज की रिपोर्टिंग दुनिया भर में भेजी, जिससे ब्रिटिश सरकार की वैश्विक स्तर पर कड़ी आलोचना हुई। इस आंदोलन के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पहली बार पश्चिमी मीडिया की प्रमुख सुर्खियों में आया। इसी वर्ष 1930 में टाइम मैगज़ीन ने गांधीजी को 'मैन आफ द इयर' घोषित किया और उनकी तुलना एक संत से की। बहरहाल, यहां यह भी गौरतलब है कि धरासना सत्याग्रह 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान हुआ एक महत्वपूर्ण अहिंसक आंदोलन था और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू और अब्बास तैयबजी ने किया था। सत्याग्रहियों ने गुजरात के धरासना नमक कारखाने की ओर शांतिपूर्ण मार्च किया, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने निहत्थे लोगों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद सत्याग्रही अहिंसा पर डटे रहे। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की कठोरता को दुनिया के सामने उजागर किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति बढ़ाई।

गांधी-इरविन समझौता:-

आंदोलन के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को अंततः भारतीय नेताओं से बातचीत करनी पड़ी। जनवरी 1931 में गांधीजी को जेल से रिहा किया गया और उन्होंने भारत के वायसराय लार्ड इरविन से बातचीत की। इसके परिणामस्वरूप गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से समाप्त किया गया तथा इसके बाद गांधीजी ने अगस्त 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। हालांकि, यह सम्मेलन बहुत सफल नहीं रहा, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने गांधीजी को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसे न तो दबाया जा सकता था और न ही नजरअंदाज किया जा सकता था।

अंत में, निष्कर्ष के तौर पर यही कहूंगा कि दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक युगांतरकारी घटना साबित हुई। कहना ग़लत नहीं होगा कि नमक जैसे साधारण मुद्दे ने जाति, धर्म और वर्ग की सभी दीवारों को तोड़कर पूरे देश को एकजुट कर दिया था। वास्तव में, इस आंदोलन ने गांधीजी के अहिंसक प्रतिरोध और सत्याग्रह के सिद्धांत को वैश्विक पहचान दिलाई और ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक नींव को गहरा झटका दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो, गांधी जी के दांडी मार्च ने भारतीयों में आज़ादी के प्रति अटूट विश्वास और संघर्ष की नई ऊर्जा भर दी थी तथा यह संकेत दे दिया था कि देश की स्वतंत्रता अब दूर नहीं रही।

नीतीश की विदाई या जदयू का सफाया (आलेख : राजेंद्र शर्मा)

नाटक के पहले अंक में, बिहार के मुख्य मंत्री पद पर बने रहते हुए, नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए चुनाव के लिए अपना पर्चा भरा। यह पर्चा भरे जाने के संबंध में दो बातें खास तौर पर गौर करने वाली थीं। पहली, यह पर्चा नीतीश कुमार की अपनी पार्टी, जदयू के मंझले दर्जे के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुखर तथा काफी व्यापक विरोध के बावजूद भरा गया। इस विरोध की शुरूआत, राज्यसभा के रास्ते से नीतीश कुमार की बिहार से विदाई की खबरें आने के साथ ही हो गयी थी। वास्तव में इस मुखर विरोध को शांत करने के लिए और बिहार से अपनी विदाई के लिए, बिहार में गठजोड़ सरकार में अपनी सहयोगी, भाजपा को अपने समर्थकों का निशाना बनने से बचाने के लिए, नीतीश कुमार ने यह अजीबो-गरीब बयान भी दिया था कि उनकी ही इच्छा थी कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी देश की सेवा करें। वैसे बिहार में सरकार और पार्टी को उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जाहिर है कि उनके इस बयान का कम-से-कम जदयू कार्यकर्ताओं की निराशा पर कोई असर नहीं पड़ा। हां! भाजपा को जरूर आलोचनाओं से अपने को बचाने के लिए कुछ सहारा मिल गया।

नीतीश कुमार के राज्यसभा का पर्चा भरने के संबंध में दूसरी खास बात थी, इस मौके पर देश के गृहमंत्री और भाजपा में मोदी के बाद नंबर दो माने जाने वाले, अमित शाह का नीतीश कुमार की बगल में खड़े रहना। इस मौके पर अमित शाह की उपस्थिति एक प्रकार से इसकी याद दिलाने के लिए भी थी कि बिहार की सत्ता में आम तौर पर तथा जदयू में खासतौर पर यह संक्रमण, उनके ही चाणक्य नीति लक्ष्यों के पूरे होने का इशारा कर रहा था। जाहिर है कि खुद अपने हाथों से फैसलों को लागू कराने में विश्वास करने वाले और नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विश्वासपात्र, अमित शाह इस मौके पर खुद उपस्थित रहकर यह तो खैर सुनिश्चित कर ही रहे थे कि भाजपा के मनमाफिक कार्ययोजना बिना किसी दिक्कत के अमल में लाई जाए और उसे जमीन पर उतारने में आखिरी वक्त पर कोई अड़चन नहीं आने पाए।

इसी नाटक के दूसरे अंक में, जाहिर है कि पूर्व-योजना के अनुसार, पटना में जदयू कार्यालय में बड़ी धूम-धाम के साथ नीतीश कुमार के पुत्र, निशांत कुमार की राजनीतिक पारी की शुरूआत का ऐलान किया गया। नीतीश कुमार के बाद, जदयू के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री, ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी। हालांकि, औपचारिक तौर पर यह मौका निशांत कुमार के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का था, लेकिन इसमें न तो निशांत कुमार को कोई शक था और न उन्हें पार्टी का सदस्य बनाने वालों को कि, वास्तव में यह उनके पार्टी का नेतृत्व संभालने का मौका था। इस मौके पर अपने संबोधन में निशांत कुमार ने जिस तरह, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करने का आश्वासन देने के बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार, पार्टी को मजबूत करने का भरोसा दिलाया, वह पार्टी का नेतृत्व संभालने के मौके के अनुरूप था। और जनता के दिल में घर बनाने की कोशिश करने का उनका आश्वासन तो, यह साफ ही कर देता था कि वह इस आयोजन को पार्टी की गद्दी ही सौंपे जाने के मौके की तरह देख रहे थे।

याद दिला दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के, जाहिर है कि भाजपा अनुमोदित पैकेज के हिस्से के तौर पर, निशांत कुमार को बिहार सरकार में महत्वपूर्ण और जदयू की ओर से संभवतः सबसे महत्वपूर्ण पद सौंपे जाने की चर्चा, पहले ही चल रही थी। इन अनुमानों में आम तौर पर जानकारों की यह राय रही है कि उन्हें उप-मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद भाजपा को दिलवाया जाना तो इस पूरी कसरत का असली मकसद ही है। प्रसंगवश इसका जिक्र भी कर दें कि निशांत कुमार के 'राज्यारोहण' के समय तक, जदयू कार्यकर्ताओं का असंतोष शांत नहीं हुआ था। इस मौके पर भी जदयू कार्यालय में, पार्टी कार्यकर्ताओं के एक हिस्से और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के समर्थकों में, बाकायदा मार-पीट हुई। याद रहे कि जदयू कार्यकर्ताओं का अच्छा-खासा हिस्सा इस सारे बदलाव को, नीतीश कुमार और जदयू के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखता है, जिसे पर्दे के पीछे से केंद्र सरकार तथा भाजपा संचालित कर रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की जदयू और नीतीश कुमार के प्रति वफादारी पर संदेह जताए जाते रहे हैं।

यह भी याद दिला दें कि बिहार में यह सत्ता संक्रमण किसी भी तरह से अप्रत्याशित नहीं है। वास्तव में, पिछले साल राज्य में विधानसभा चुनाव के मौके पर तो लगातार ही विपक्ष की ओर से यह सवाल उठाया जाता रहा था कि क्या भाजपा, चुनाव के बाद गठबंधन के कामयाब होने की सूरत में, अगले पांच साल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगी? विपक्ष ही नहीं, अनेक टिप्पणीकारों के भी इस आशय के सवालों के बावजूद, भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान काफी वक्त तक इस सवाल का स्पष्ट उत्तर देने से बचती ही रही थी। इसके बजाय भाजपा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़े जाने पर जोर देती रही थी, लेकिन इसे विशेष रूप से महाराष्ट्र के अनुभव की रौशनी में, चुनाव में जीत के बाद भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर, संदेह बनाए रखने का ही इशारा माना जा रहा था।

पाठकों को याद ही होगा कि महाराष्ट्र में गठजोड़ सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधानसभाई चुनाव लड़े जाने के बाद, विधानसभा में अपनी ताकत ज्यादा होने के तर्क से भाजपा ने, मुख्यमंत्री पद खुद अपने नाम कर लिया था और शिंदे को धकेल कर उप-मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा दिया था। स्वाभाविक रूप से बिहार में पूछा जा रहा था कि यह मानने का क्या आधार है कि भाजपा, महाराष्ट्र के इस पैंतरे को बिहार में भी नहीं आजमाएगी। उल्टे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ते सवालों के बीच, इसकी अटकलों को और बल ही मिल रहा था कि चुनाव में जीत मिली तो भाजपा, अपना मुख्यमंत्री बनवाएगी।

वास्तव में ये आशंकाएं बिहार में 2020 के आखिर में हुए चुनाव के नतीजे में, सत्ताधारी जदयू-भाजपा गठजोड़ में ताकतों के संतुलन में हुए बदलाव की भी निरंतरता में थीं। यह बिहार में पहली गठजोड़ सरकार थी, जिसमें दो उप-मुख्यमंत्री थे, जो दोनों ही भाजपा से थे। और कार्यकाल के बीच में ही जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर, राजद के साथ गठबंधन सरकार बनाई, वह सरकार तो कुछ महीने ही चली और उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर पल्टी मारकर भाजपा के साथ गठजोड़ में पहुंच भी गए, लेकिन उसके बाद सिर्फ नीतीश कुमार के प्रति भाजपा का अविश्वास ही नहीं बढ़ा था, गठजोड़ सरकार में ताकतों का संतुलन भाजपा ने अपने पक्ष में और भी झुका लिया था। इसके बावजूद, चार महीने पहले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के फौरन बाद, बहुतेरे अनुमानों के विपरीत भाजपा ने मुख्यमंत्री पद पर अधिकार की मांग तो नहीं की, पर उसने सरकार में ताकत का संतुलन और ज्यादा अपने पक्ष में झुका लिया। इसमें विधानसभा के स्पीकर का पद हासिल करने का विशेष रूप से रणनीतिक महत्व था।

और अब चार महीने बाद ही भाजपा ने, मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए अपना दांव चल दिया है। फिर भी यह सिर्फ नीतीश कुमार की बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, बीस साल लंबी पारी के अंततः खत्म होने का ही मामला नहीं है। यह इसका भी मामला नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद जदयू के हाथ से निकलकर, अब भाजपा के हाथ में पहुंच गया है। यह उस दिलचस्प और मारक पैटर्न का हिस्सा है, जो हर जगह क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भाजपा के रिश्तों में देखने को मिलता है। जिन राज्यों में मुख्य राजनीतिक विभाजन, कांग्रेस और उसके विरोध में सामने आयी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच रहा है, उन राज्यों में पांव जमाने के लिए भाजपा, पहले जूनियर पार्टनर के तौर पर इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठजोड़ करती है। उसके बाद, ऐसे हरेक मामले में अरब और उसके ऊंट वाले किस्से को दोहराया गया है, जिसमें ऊंट सर्दी के बचने के लिए थोड़ा-थोड़ा कर के तंबू में घुसने की इजाजत मांगता है और होते-होते होता यह है कि ऊंट तंबू में और अरब तंबू के बाहर।

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, असम में असम गण परिषद, जम्मू-कश्मीर में पीडीपी, महाराष्ट्र में शिव सेना का यही अनुभव रहा है, जो अब बिहार में भी दोहराया जा रहा है। हां! यह खेल हमेशा समान रूप से कामयाब ही रहा हो, ऐसा भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में, ये तजुर्बे संघ-भाजपा के लिए कहीं मुश्किल साबित हुए हैं। फिर भी कुल मिलाकर, पैटर्न यही है कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ कर के सत्ता तक पहुंच बनाने के बाद, संघ-भाजपा जोड़ी अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के ही आधार को हड़प कर जाती है और सहयोगी पार्टियों को निगल ही जाती है या उन्हें पूरी तरह से पंगु बनाकर छोड़ देती है। हैरानी की बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार की विदाई बाद, संघ-भाजपा जोड़ी विभिन्न तरीकों से जदयू को भी इसी रास्ते पर लगा दे।

लेकिन, किसी एकाधिकारी प्रकृति की, वास्तव में फासीवादी प्रकृति की राजनीतिक पार्टी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जहां गठबंधन का आधार ही किसी न किसी तरह सत्ता में हिस्सा हासिल करना होता है, न कि सहयोगी पार्टियों के साथ जनहित के किसी साझा कार्यक्रम को पूरा करना। इन तमाम वर्षों में हमारे देश में वामपंथी पार्टियों के नेतृत्व वाले गठबंधन ही बाद वाली प्रकृति के गठबंधन साबित हुए हैं, जो सहयोगियों के आधार की कीमत पर अपना विस्तार करने की नहीं, सहयोगियों के साथ मिलकर साझा आधार को बढ़ाने की रणनीति पर चलते हैं। इसीलिए, वामपंथी नेतृत्ववाले गठबंधन ज्यादा मजबूत तथा सदाबहार साबित होते हैं, जबकि भाजपा के गठबंधन 'यूज एंड थ्रो' और 'यूज एंड डाइजेस्ट' के ही उदाहरण साबित हुए हैं। नीतीश कुमार जिस सत्ता को अपने बेटे को उत्तराधिकार में सौंपने के लिए, शाह प्रायोजित संक्रमण योजना के साझीदार बने हैं, वह सत्ता पूरी तरह संघ-भाजपा के कब्जे में आने में अब शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'लोकलहर' के संपादक हैं।)

तुम और बच्चे मेरी ज़िंदगी की सबसे जीवंत तस्वीर बन गए हो....

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह

मुश्ताक़ को अपना बचपन याद आया वो दिन जब कंधों पर स्कूल का भारी बस्ता होता था, न कि ज़िम्मेदारियों का पहाड़। फ़ोटोग्राफ़ी उनका जुनून था। पुराने दोस्त अशोक के साथ मिलकर उसने एक पुराना, कैमरा खरीदा था। दोनों गांव की टेढ़ी-मेढ़ी गलियों, ढलते सूरज की लालिमा और नदी किनारे खिलते कमल की तस्वीरें लिया करते। अशोक हँसते हुए कहता, ₹मुश्ताक़, तू एक दिन दुनिया का मशहूर आर्टिस्ट बनेगा! तेरी लेंस से वो नज़ारे कैद होंगे जो आँखें भी न देख सकें।₹ लेकिन वालिद साहब की थकान, उम्र और घर की माली हालत ने उस कैमरे को अलमारी के धूल भरे कोने में दफ़ना दिया। आज भी, जब मुश्ताक़ किसी युवा को कैमरा लिए सड़क पर देखते, तो दिल में एक गहरी टीस उठती, वो कलाकार मुश्ताक़ कहीं खो गया था, बचा था तो सिर्फ़ एक साधारण क्लर्क, ज़रूरतों का ग़ुलाम।सलमा की ममता का आलम ख़यालों की इस मशगूल दुनिया से उन्हें पत्नी सलमा की मधुर आवाज़ ने ,अपनी तरफ़ मुतवज्जो किया। ₹मुश्ताक़ साहब, चाय ठंडी हो रही है। आँखें बंद करके क्या ख़्वाब बुन रहे हो?₹ मुश्ताक़ ने आँखें खोलीं। सामने सलमा खड़ी थीं, उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक, लेकिन वक्त की चक्की ने झुर्रियाँ उकेर दी थीं। बालों पर कुछ चांदी सी चमक नज़र आने लगी थी, शादी के वक़्त सलमा का चेहरा खिले गुलाब सा हुआ करता था, घने काले बाल

और लाली भरी हँसी। देखते ही बनती थी, अब हाथ सख़्त हो चुके थे घर की मेहनत से, लेकिन आँखों में वही वफ़ा झलक रही थी।

मुश्ताक़ ने उनका हाथ थामा, आवाज़ में उदासी घुली हुई, ₹सलमा, तुम भी कितना थक गई हो। बच्चों की परवरिश, माँ-बाप की ख़िदमात में, तुमने कभी अपना हक़ से कुछ नहीं माँगा।₹ सलमा मुस्कुराईं, आँखें नम हो गईं ₹अरे जनाब, थकान क्या चीज़ है? जब तक आपकी नज़रों में परिवार की फ़िक्र है, मेरी रूह में सुकून बस्ता है। हम एक कश्ती के साथी हैं, आप लड़खड़ाओगे तो मैं संभालूँगी, मैं थकूँगी तो आपका ये प्यार मेरा सहारा बनेगा।₹ सलमा ने मुश्ताक़ का हाथ छुआ, तो बरसों की थकान हवा में उड़ गई। मुश्ताक़ बोले, ₹सच कहती हो। मेरे फ़ोटोग्राफ़ी के सपने अधूरे रह गए, लेकिन तुम और बच्चे मेरी ज़िंदगी की सबसे जीवंत तस्वीर बन गए हो।₹ रात की ख़ामोशी में उन्हें एहसास हुआ, ज़िम्मेदारियाँ बोझ नहीं, बल्कि प्यार का वो सबूत हैं जो दिल को अमर बनाते हैं। परिवार का सुकून भरा माहौल था, वे दोनों आंगन से कमरे में पहुँचे, जहाँ उनका बेटा समीर और उनका पोता रमीज़ अपनी छोटी सी बाइक चलने में मशगूल था, दौड़ कर मुश्ताक की गोदी में आकर बैठ गया, मानो सारी दुनिया की दौलत उसको मिल गई थी, वो बड़ा पुरसुकून सा अपने दादा की गोद में बैठा मुस्कुरा रहा था, कल ही सलमा शहर से अपने पोते के लिए बाइक खरीद कर लाई थी, मुश्ताक़ अहमद के चेहरे से थकान ग़ायब हो चुकी थी। उन्होंने बेटी को पुकारा, ₹बेटा, आओ तुम भी। दादा-दादी ने खाना खा लिया?₹ बेटी की आवाज़ आई, ₹जी पापा, वो पहले ही खा चुके हैं। दवाईयाँ भी ले लीं। सब ठीक है।₹ सभी एक मेज़ पर बैठे। हँसी-मज़ाक़ का दौर चला, बेटे ने नई नौकरी की बात बताई, बहू अमरीन ने घर की नई रेसिपी आज़मा कर कुछ नया बनाया था, माहौल में सुकून की लहर दौड़ रही थी, जैसे चाँदनी रात ने सबको गोद में ले लिया हो। मुश्ताक़ सोच रहे थे, कल सुबह फ़िर नया सूरज उगेगा, और वे इस परिवार की खुशियों के लिए तैयार होंगे, सपनों की कमी तो थी, लेकिन प्यार की कोई कमी न थी।

राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी खेमों में डर है

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : विपक्ष अब अपने MLAs को साथ रखने की होड़ में है। निर्मला कच्छर से लेकर डिनर पार्टी तक, सब कुछ शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इस बार राज्यसभा के लिए BJD और कांग्रेस ने अपने पार्टी MLAs को रिसॉर्ट और होटलों में रखने का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक, अगले शनिवार और रविवार को असेंबली नहीं है। इसलिए, दोनों पार्टियों के MLAs को शुक्रवार रात या शनिवार सुबह अलग-अलग किसी सीक्रेट जगह पर ले जाया जाएगा। उनके कांग्रेस शासित राज्य में जाने की संभावना है। सुनने में आया है कि PCC ने AICC से इस बारे में बात की है। राज्यसभा चुनाव सोमवार को होंगे। सूत्रों ने जानकारी दी है कि पार्टी के सीनियर लीडर उस दिन MLAs के साथ सीधे असेंबली आएंगे। पार्टी लीडरशिप के फैसले को सीधे चुनौती देने वाले सीनियर लीडर प्रवत्था बिस्वाल के जाने और आज पूर्व MP रवींद्र जेना के इस्तीफे के बाद से BJD पॉलिटिक्स में हलचल मची हुई है। कुछ MLAs को लेकर पार्टी के अंदर टकराव हो गया है। पार्टी के अंदर करीब 5 MLAs के क्रॉस वोटिंग करने की चर्चा है। पार्टी इन MLAs पर कड़ी नजर रख रही है।

हालांकि, कुछ लोग पार्टी से दूरी बनाए हुए बताए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया में ऐसे बयान भी दिए हैं जिससे पार्टी कंफ्यूजन में है। BJD सुप्रीमो नवीन पटनायक अब MLAs को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर MLAs को नवीन के घर पर बुलाकर बातचीत की जा रही है। आज 10 से ज़्यादा MLAs को बुलाया गया था। नवीन से बातचीत के बाद खबर है कि पार्टी के एक सीनियर MLA महाप्रभु का निर्मल्य प्रसाद लेकर एक-एक करके MLAs को शपथ दिला रहे हैं। इसी तरह, कांग्रेस पार्टी भी कल से होटल में MLAs के साथ मीटिंग और डिनर पार्टी कर रही है। PCC प्रेसिडेंट भक्त दास और MLA लीडर रामचंद्र कदम सभी से कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं। हालांकि, पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी की बात भी है। कल MLA मीटिंग में शामिल हुए 2 MLAs के बाद भी वे स्टार होटल में ऑर्गनाइज्ड डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए। पार्टी के 3 MLAs को लेकर काफी चर्चा हो रही है ।कटक बाराबती MLA सोफिया फिरदौस, जो एक दिन पहले MLA मीटिंग और नॉमिनेशन फाइलिंग से गैरहाजिर थीं, ने मीडिया से कहा, ₹मैं राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के फैसले के साथ हूं।₹ एक सीनियर MLA के मुताबिक, वोट पहले की तरह सीक्रेट नहीं होगा। वोट अपनी पार्टी के एजेंट को दिखाना होगा। फिर, जिन्होंने पार्टी से अलग जाने का फैसला किया है, वे क्रॉस वोटिंग करेंगे। फिर, अगर वोट पार्टी एजेंट के साथ बूथ पर मौजूद सभी लोगों को दिखाया गया, तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। इसका भी डर है। वोटिंग के दिन गैरहाजिर रहकर वोटों की संख्या कम करने की पार्टी की साजिश को भी नाकाम करना होगा।

राउरकेला विधानसभा चुनाव मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

विजयी प्रत्याशी पर गलत हलफनामा देने व जानकारी छुपाने का आरोप
डॉ. राजकुमार यादव ने न्याय की लगाई गुहार

राउरकेला: वर्ष 2024 के राउरकेला विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। विजयी प्रत्याशी शारदा नायक द्वारा कथित रूप से गलत हलफनामा (एफिडेविट) देने और महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने के आरोप को लेकर यह मामला दायर किया गया है। स्थानीय युवा नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल करने वाले डॉ. राजकुमार यादव ने न्याय की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जो डायरी संख्या 14417/2026 के तहत प्रस्तुत की गई है।

इससे पहले डॉ. यादव ने इलेक्शन पिटिशन नंबर 1/2024 के तहत उच्च न्यायालय में भी मामला दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विजयी प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में संपत्ति और आपराधिक मामलों से जुड़ी पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी और कुछ तथ्यों को छुपाया।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को नामांकन के समय अपनी संपत्ति, लंबित मामलों और अन्य विवरणों की पूरी और सही जानकारी हलफनामे में देना अनिवार्य होता है। गलत जानकारी देना या जानकारी छुपाना गंभीर आरोप माना जाता है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि अदालत इस मामले में त्रुटि पाती है, तो संबंधित जनप्रतिनिधि की सदस्यता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में भी चर्चा तेज हो गई है और लोगों की नजर अब अदालत के फैसले पर टिकी हुई।

पड़ोसियों को एफडीआई के नियमों में मिली ढील के आर्थिक व कूटनीतिक मायने

कमलेश पांडेय

भारत-चीन के कभी नरम, कभी गरम सम्बन्धों से अक्सर प्रभावित होने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के लिए एक अच्छी खबर है जो उद्यमियों को सुकून देने वाली है। वह यह कि भारत सरकार ने 'भूल' सुधार करते हुए मार्च 2026 में पड़ोसी देशों यथा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान के लिए एफडीआई (FDI) नियमों में ढील दी है। इस प्रकार पड़ोसियों को एफडीआई के नियमों में मिली ढील के आर्थिक व कूटनीतिक मायने स्पष्ट हैं। उम्मीद है कि भरोसेमंद आर्थिक रिश्ते पुनः गुलजार होंगे।

उल्लेखनीय है कि यह बदलाव 2020 के प्रेस नोट 3 के कड़े प्रावधानों में संशोधन के रूप में आया जिसमें पहले इन देशों से सभी निवेशों के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी थी।

ऐसे में दो टूक सवाल है कि आखिर एफडीआई में मुख्य रूप से क्या-क्या बदलाव हुए हैं ? तो यह जानलिजिए कि अब 10% तक के गैर-नियंत्रणकारी शेयरहोल्डिंग वाले निवेश ऑटोमैटिक रूट से हो सकेंगे बशर्ते सेक्टरल कैप्स का पालन हो। गौरतलब है कि इससे पहले सभी एफडीआई के लिए पूर्वानुमति अनिवार्य थी।

बताया जाता है कि सरकार का यह नया कदम विभिन्न सेक्टर्स में निवेश को आसान बनाता है। इसलिए पूरक सवाल यह है कि आखिर इस ढील देने के कारण क्या हैं ? क्या आतंकवाद, उग्रवाद और पड़ोसियों से विघटनकारियों को शह देने-दिलाने की हरकतें कम हो गईं, या फिर ईरान-इजरायल युद्ध से पड़ोसियों से सदैव अच्छे रिश्ते बनाये रखने की सीख मिली ! शायद दोनों बात हो या कोई भी नहीं हो ! वैसे तो अर्थकूटनीति के जानकारों ने बताया है कि सरकार ने व्यापार विस्तार को बढ़ावा देने और व्यवसायिक लेन-देन को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।

ऐसा इसलिए कि चीन से सम्बन्धों में सुधार आया है और पाकिस्तान-, बंगलादेश की हेकड़ी भी टूट चुकी है। वहीं अफगानिस्तान से भरोसा बहाल हुआ है।

उल्लेखनीय है कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद लगाए गए प्रतिबंधों से कई प्रोजेक्ट्स अटक गए थे, जिसे ठीक करने का यह समयानुकूल प्रयास है। इससे विदेशी निवेश में वृद्धि की उम्मीद है। चूंकि प्रभावित देश में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि शामिल थे, इसलिए यह दूरदर्शिता भरा कदम है। यह नीतिगत संशोधन प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट बैठक में मंजूर हुआ।

दरअसल, नए एफडीआई के नियमों में भारत सरकार ने 2020 के प्रेस नोट 3 के तहत पड़ोसी देशों यानी चीन, पाकिस्तान आदि से आने वाले निवेशों के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब 10% तक के गैर-नियंत्रणकारी निवेश ऑटोमैटिक रूट से स्वीकृत हो सकेंगे। यह बदलाव मार्च 2026 में कैबिनेट द्वारा मंजूर हुआ। अब 10% स्टेक पर ऑटोमैटिक अप्रूवलः इन देशों से 10% तक नॉन-कंट्रोलिंग स्टेक (शेयरहोल्डिंग) अब बिना सरकारी मंजूरी के अनुमत है।

इसके लिए समयबद्ध मंजूरी मिलेगी। इससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों (स्टार्टअप्स, डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग) में निवेश प्रस्तावों पर अधिकतम 60 दिनों में निर्णय होगा। बेनेफिशियल ओनर की परिभाषा के मुताबिक, निवेशकों के वास्तविक मालिकों की पहचान के स्पष्ट मानदंड जोड़े गए। साथ ही प्रभावित देश और सेक्टर भी स्पष्ट कर दिए गए। देश में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि शामिल हैं। इससे फायदा यह होगा कि निवेश प्रक्रिया तेज होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और कंप्लायंस बोझ कम होगा। बता दें कि पहले सभी एफडीआई पर पूर्वानुमति जरूरी थी।

समझा जाता है कि इन एफडीआई नियमों में ढील से भारत को विदेशी निवेश में वृद्धि, नई तकनीकों तक पहुंच और वैश्विक सप्लाई चेन में एकीकरण जैसे आर्थिक फायदे होंगे। यह आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा और समग्र आर्थिक विकास को गति देगा। सरकार का अनुमान है कि इससे घरेलू पूंजी पूरक बनेगी। इसके निम्नलिखित प्रमुख आर्थिक लाभ होंगे।

पहला, एफडीआई प्रवाह में वृद्धिः इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में पड़ोसी देशों से निवेश बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा।

दूसरा, घरेलू मूल्य संवर्धन और विस्तारः नई तकनीकें मिलेंगी, भारतीय फर्में बढ़ेंगी और मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी।

तीसरा, व्यापार घाटा कमः चीन जैसे देशों से आयात के बजाय निवेश से व्यापार संतुलन सुधरेगा।

चौथा, दीर्घकालिक प्रभावः निवेश आकर्षणः ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, 8.8 लाख करोड़ की अटकी परियोजनाओं को गति मिलेगी।

पांचवां, राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षितः 10% तक सीमित रखते हुए रणनीतिक क्षेत्रों पर निगरानी बरकरार रहेगी।

उम्मीद है कि यह बदलाव भारत को निवेश और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा। बताते चलें कि भाजपा के ही पूर्वप्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा था कि हम इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन भूगोल नहीं ! हालांकि मेरा अनुभव बताता है कि इतिहास और भूगोल सदैव नायक बदलते आये हैं और लोकतांत्रिक नायकों से ज्यादा उम्मीदें बेमानी होती हैं, क्योंकि उनकी सत्ता शक्ति से नहीं, बल्कि खलनीति आधारित बहुमत से बदलती हैं, इसलिए मूल समस्या जस की तस बनी रहती है और उनमें आंशिक बदलाव दृष्टिगोचर होता है। खैर, राष्ट्रहित और जनहित के सभी बदलाव स्वागत योग्य हैं।(युवराज फीचर्स)

कार्यमंगलम बडेर में हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ श्री विनायक थाली कार्यक्रम

परिवहन विशेष न्यूज

कार्यमंगलम: सीरवी समाज कार्यमंगलम बडेर में बुधवार को श्री विनायक थाली महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मंगलवार शाम को राजस्थान से आए संत सत्यप्रकाश महाराज के सानिध्य में स्थानीय भजन कलाकारों द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। संस्था के सभी सदस्यों ने सपरिवार उपस्थित होकर भजन संध्या का लाभ लिया। बुधवार सुबह मां आईजी के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर आरती की गई तथा गणेश भगवान की पूजा-अर्चना के साथ श्री विनायक थाली कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सदस्यों, नजदीकी बडेर की कार्यकारिणी, महिला सेवा मंडल, नवयुवक मंडल, बोलियों के लाभार्थी भामाशाहों एवं समाज के विभिन्न सेवादायी संगठनों का संस्था की ओर से स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम बोली के लाभार्थी राकेश सीरवी ने माला, साफा एवं शाल ओढ़ाकर किया गया। संस्था के अध्यक्ष नेमाराम पंवार ने सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। वहीं सचिव पेमाराम चोयल ने अन्य संस्थाओं के सहयोगी बंधुओं के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष कानाराम पंवार, नवयुवक मंडल अध्यक्ष मोहनलाल, गेर मंडल अध्यक्ष नरेश, महिला मंडल अध्यक्ष मोहिनी देवी, सचिव कमला देवी सहित संस्था के सभी सदस्य सपरिवार उपस्थित रहे।

झारखंड ईडी कार्यालय में पुलिस मारपीट पर हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को ईडी बनाम झारखंड पुलिस विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखे गए आदेश के तहत आज सुनाया।अपने फैसले में अदालत ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़े पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।

कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार और रांची पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मचारी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई ।संतोष कुमार ने आरोप लगाया था कि 12 जनवरी को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

उसने यह भी कहा था कि पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसी शिकायत के आधार पर रांची के एयरपोर्ट थाना में ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी ।एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ईडी कार्यालय भी पहुंची और जांच के नाम पर कार्रवाई की, जिससे केंद्रीय एजेंसी और राज्य पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। ईडी ने रांची पुलिस की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। एजेंसी का कहना था कि राज्य पुलिस की कार्रवाई से केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है। इससे पहले 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

उस समय अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी केंद्रीय एजेंसी के काम में इस तरह हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अदालत ने ईडी कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआईएसएफ, बीएसएफ या अन्य अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा की जिम्मेदारी देने का निर्देश भी दिया था। साथ ही परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया था।

15 जनवरी को जांच के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने विस्तृत दलीलें रखीं। ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू, अधिवक्ता एके दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।

वहीं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागामुथु, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता दीपांकर ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। शिकायतकर्ता संतोष कुमार की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए इसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी करेगी।

ओड़िया शास्त्रीय भाषा दिवस पर सरायकेला बार अध्यक्ष ,सचिव को ओड़िया पाठ्य पुस्तक अर्पित

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

सरायकेला, ओड़िया शास्त्रीय भाषा दिवस के अवसर पर सरायकेला के दो महत्वपूर्ण विद्यालयों में इस भाषा की पठन पाठन सुविधा, भाषा संरक्षण और प्रसार के उद्देश्य से एक अभिनव प्रयास हुआ है । 11 मार्च ओड़िया शास्त्रीय भाषा दिवस अवसर पर सरायकेला बार के अध्यक्ष एवं सचिव को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सम्मानित करने के तत्पश्चात कार्तिक परिच्छा द्वारा अध्यक्ष श्री महतो एवं सचिव देवाशीष ज्योतिष को एक पत्र लिखकर करीब तीन दर्जन ओड़िया पाठ्य पुस्तकों का सेट भेंट किया। जिन महान विभूतियों की स्मृति व सम्मान में यह कदम उठाया गया है उसमें - राजकुमार टिकायत नृपेंद्र नारायण सिंहदेव जिन्होंने अपने विधायकी काल में बिहार विधानसभा में ओड़िया भाषा में पांच वर्ष तक बोलते रहे , राजकुमार कुंवर विजय प्रताप सिंहदेव जिन्होंने अपना आलीशान महल नारी शिक्षा निमित्त दे दिया था तथा स्वर्गीय ज्योति लाल परिच्छा जिन्होने ओड़िया भाषा , साहित्य , संस्कृति संरक्षण एवं सरायकेला राज्य में इंजिनियरिंग के क्षेत्र में महत्व पूर्ण कार्य कर टिकायत नृपेन्द्र नारायण के निकटतम सहयोगी में से रहे । उन महान विभूतियों की स्मृति में ओडिशा स्कूली टेक्स बूक की ओड़िया पाठ्य पुस्तकें बुधवार को प्रदान की गईं।

इस अवसर पर कार्तिक परिच्छा ने एक ज्ञापन सौंपते हुए बार से निवेदन पूर्वक कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 350 (ए) में अपनी मातृभाषा मे शिक्षा की सुविधा के लिए दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश को अमलीजामा पहनाया जाए । परिच्छा ने लिखा है जो विद्यार्थी ओड़िया पढ़ रहे हैं पर उनके पास ओड़िया पाठ्य पुस्तकें नहीं है। उनकी तकलीफ देखते हुए इन ओड़िया किताबों को दी जा रही है । श्री परिच्छा ने सरायकेला के नृपराज राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय तथा कुमार विजय विजय प्रताप गर्ल्स उच्च विद्यालय में वर्ग 9, 10 एवं 11 में करीब तीन दर्जन ओड़िया पाठ पुस्तक उपलब्ध कराया गया है । सनद रहे कि नृपराज विधालय राजा नृपराज के नाम से नामित है जहां कभी यहां 10-12 ओड़िया शिक्षक हुआ करते थे । ओड़िया समेत विभिन्न भाषा विषय आदि के पठन पाठन से जुड़े थे आज स्थिति ठीक विपरित है ।

अन्तिम शासक राजा आदित्य प्रताप सिंहदेव के पौत्र सिंह भानू सिंहदेव तथा कुंवर विजय प्रताप सिंहदेव के पुत्र कामाख्या सिंहदेव तथा ज्योति लाल परिच्छा के पौत्र कार्तिक कुमार परिच्छा ने इस आवेदन पर हस्ताक्षरित कर महामहिम राष्ट्रपति तथा झारखंड एवं ओडिशा के मुख्यमंत्री को भी इसकी प्रति देते हुए निवेदन किया है ।

आवेदन में आग्रह किया है कि बार एसोसिएशन जिला सत्र न्यायाधीश सरायकेला के माध्यम से तमाम किताबें उपायुक्त सरायकेला को प्रदान कर छात्र छात्राओं में संविधान वर्णित मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण का अधिकार को बरकरार रखवाने का कष्ट करें ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023